सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 03

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी शुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

विषय सूची

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे	1-14
सप्ताह के चर्चित व्यक्ति	15-18
सप्ताह के चर्चित स्थान	19-21
सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस	22-25
ब्रेन बूस्टर	26-33
स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	34-38
स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)	39-40

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- रज पर्व अथवा राजा परबा उत्सव

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- तुलु (Tulu) भाषा
- 47वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2021
- दुर्लभ मृदा तत्व
- दिल्ली मास्टर प्लान 2041 : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- शिक्षा मंत्रालय का ऑनलाइन मॉड्यूल

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- महाराष्ट्र में पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा
- CHIME टेलीस्कोप एवं फास्ट रेडियो बर्स्ट
- संयुक्त राष्ट्र में 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च-स्तरीय संवाद'
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल
- नागालैंड में नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का 'बीड मॉडल'
- ऑपरेशन ओलिविया
- पासिफए (PASIPHAE) परियोजना
- शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. रज पर्व अथवा राजा परबा उत्सव

चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा में राजा परबा उत्सव का समापन हो गया है। यह उत्सव नारीत्व पर केन्द्रित है।

प्रमुख बिन्दु

- उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है- मासिक धर्म। ओडिशा में धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान तीन दिन के मासिक धर्म पर होती हैं, और मानसून आते ही भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है।
- धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है।

राजा परबा

- यह ओडिशा में नारीत्व का जश्न मनाने का तीन दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार के दूसरे दिन मिथुन के सौर महीने की शुरुआत होती है, जब बारिश का मौसम शुरू होता है।
- ऐसा माना जाता है कि पहले तीन दिनों में धरती माता मासिक धर्म से गुजरती है। चौथे दिन को वसुमती स्नान या भूदेवी का औपचारिक स्नान कहा जाता है।

त्यौहार मनाने का तरीका

- इस पर्व के लिए घर की साफ-सफाई की जाती है। बाग-बगीचों में झूले लगाए जाते हैं। पहले तीन दिनों तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पहले दिन को पहिली राजा कहते हैं, दूसरे दिन को मिथुना संक्रांति कहा जाता है, तीसरे दिन को दाहा कहा जाता है जबकि चौथे दिन को वसुमती स्नान कहते हैं। जिस दिन महिलाएं भूमि के प्रतीक के रूप में पीसने वाले पत्थर को हल्दी के लेप से स्नान कराती हैं। भूमि को सभी प्रकार के मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं।

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2. तुलु (Tulu) भाषा

चर्चा का कारण

- हाल ही में दक्षिण भारत में तुलु (Tulu) भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग जोर पकडती जा रही है।

मुख्य बिन्दु

- दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा केरल राज्यों में तुलु (Tulu) भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है।
- इन राज्यों के लोग तुलु (Tulu) भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में देखना चाहते हैं।
- इसके अलावा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों के लोग तुलु भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

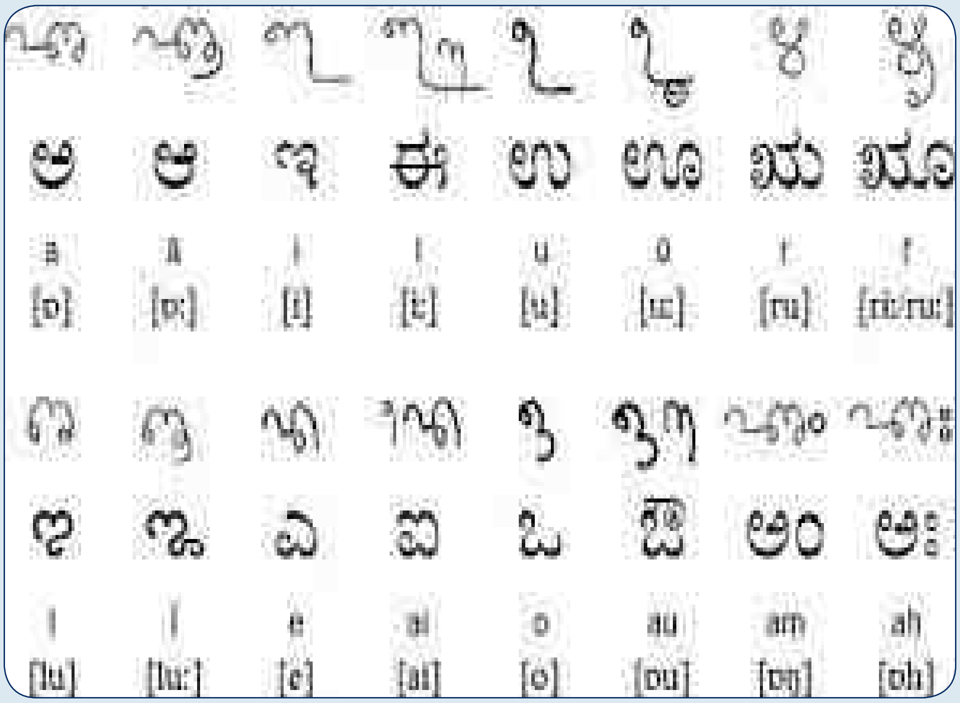

तुलु (Tulu) भाषा के बारे में

- तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने वाले लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में तुलु बोलने वाले लोगों की संख्या 18,47,427 है। जो कि आठवीं अनुसूची में सम्मिलित मणिपुरी और संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग से भी ज्यादा है। रोबर्ट काल्डवेल (1814-1891) ने द्रविड़ भाषाओं का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा था जिसमें बताया गया था कि तुलु द्रविड़ परिवार की सर्वाधिक विकसित भाषाओं में से एक है। जिन क्षेत्रों में तुलु भाषा प्रधानत: बोली जाती है उसे बोलचाल की भाषा में तुलु नाडु कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय जिले और केरल का कासरगोड जिला आता है। केरल के कासरगोड जिले को सप्तभाषा संगम भूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तुलु समेत सात भाषाओं का संगम देखने को मिलता है। वस्तुत: कासरगोड के साथ-साथ मंगलुरु और उडुपी नगर भी तुलु संस्कृति के गढ़ माने जाते हैं।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं के विषय में जानकारी दी गयी है। वर्तमान समय में आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि संविधान निर्माण के समय 14 भारतीय भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1967 में सिन्धी भाषा को अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। वर्ष 2004 में बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया।
- इस प्रकार वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

3. 47वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2021

चर्चा का कारण

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47वें जी-7 शिखर सम्मेलन 2021 सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने की।

सम्मेलन के प्रमुख बिन्दु

- जी-7 शिखर सम्मेलन में "अतिथि देशों" के रूप में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया।
- इस वर्ष 'बिल्ड बैक बेटर' विषय पर चर्चा की गयी, जिसके अंतर्गत भविष्य में आने वाली महामारियों के खिलाफ लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, कोरोनवायरस से लड़ना; मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना; जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना आदि विषय शामिल थे।
- अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ खुराकें दान देने का संकल्प लिया है और व्यापक एवं तीव्र गति से टीकाकरण करने की खातिर सम्पन्न देशों से समन्वित प्रयास करने को कहा। वहीं बोरिस जॉनसन ने जी7 समूह में एक अरब खुराकें उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया।
- जी-7 देशों ने स्पष्ट किया कि चीन एक प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी, वैश्विक मुद्दों पर एक भागीदार और एक प्रतियोगी है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

डेमोक्रेसीज 11

- इस सम्मेलन में जी-7 और अतिथि देशों द्वारा डेमोक्रेसी 11 पर हस्ताक्षर किये गए, जो खुले समाज व लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन देशों का मानना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोगों को भय और दमन से मुक्त रहने में मदद करता है।

इंटरनेट पर भारत के विचार

- 2021 के जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ओपन सोसायटीज स्टेटमेंट' (यह शब्द फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्गसन ने दिया था, जिसका आशय बहुलतावादी समाज से होता है, जहां सभी के लिए बराबर अधिकार और आजादी होती है।) पर दस्तखत किए हैं। इसमें लिखा है कि राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन लोकतंत्र और आजादी के लिए खतरा है। हालांकि भारत का मानना है कि दुष्प्रचार और साइबर हमले इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं।

जी-7 एवं भारत

- भारत ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए 'एक धरती, एक स्वास्थ्य' (One Earth, One Health) का मंत्र दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने कोविड संबंधी प्रौद्योगिकियों पर पेटेंट छूट के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में दिए गए प्रस्ताव के लिए जी-7 के समर्थन का भी आह्वान किया।
- गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करने के लिये प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिदेय व्यय प्रतिज्ञा को पूरा करने हेतु योगदान को बढ़ाने की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया गया।
- भारत ने वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और इसमें सुधार की प्रतिबद्धता जाहिर की। साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने का संकल्प लिया। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया।

जी-7 क्या है?

- जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) भी कहते हैं।
- जी-7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक जी-7 को 'जी-8' के रूप में जाना जाता था, किन्तु वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुनः जी-7 कहा जाने लगा।
- ग्लोबल जीडीपी में जी7 देशों का 46 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा है।

4. दुर्लभ मृदा तत्व

चर्चा का कारण

- चीन और अमेरिका के बीच दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Element -REE) को लेकर तनाव बढ़ सकता है। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े खनिजों की मांग में अपेक्षित वृद्धि ने अमेरिका के साथ यूरोप पर भी अधिक दबाव डाल दिया है। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में कहा गया है कि चीन इन तत्वों के निर्यात में कमी करने की कोशिश कर सकता है।

अमेरिका एवं यूरोपीय संघ की चीन पर निर्भरता

- यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 में, अमेरिका ने चीन से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का लगभग 80% आयात किया। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी चीन से अपनी आपूर्ति का 98% दुर्लभ मृदा तत्व आयात करता है।

दुर्लभ मृदा तत्त्व

- दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते हैं। इनमें आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड और स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं।
- 15 दुर्लभ मृदा तत्व हैं- लैंथेनम (La), सेरियम (Ce), प्रेजोडियम (Pr), नियोडिमियम (छक), प्रोमेथियम (Pm), समैरियम (Sm), यूरोपियम (Eu), गैडोलिनियम (Gd), टरबियम (Tb), डिस्प्रोसियम (Dy), होल्मियम (Ho), एर्बियम (Er), थुलियम (Tm), यटेरबियम (Yb), और लुटेटियम (Lu)।

प्रयोग

- इनका प्रयोग पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान और हथियार प्रणालियों जैसे बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है।
- इनके अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्तिशील, और विद्युत-रासायनिक गुणों के कारण स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, कैमरा लेंस, एक्स-रे स्कैनर, विंड टर्बाइन और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जैसे उत्पादों के उत्पादन में आवश्यक रूप से उपयोग किया जाता हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्व अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं, जिसमें प्रमुख है धातु विज्ञान (धातु शोधन और मिश्र धातु), मोटर वाहन और पेट्रो-रसायन उद्योग में उत्प्रेरक, कांच/चीनी मिट्टी की चीजें, फास्फोरस (LED, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लैट पैनल डिस्प्ले), पराबैंगनीकिरण, रिचार्जेबल सॉलिड स्टेट बैटरी (Ni-MH), फाइबर ऑप्टिक्स और अन्य।

5. दिल्ली मास्टर प्लान 2041 : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी। इस मसौदे को सार्वजनिक कर अब नागरिकों की आपत्तियों और सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली का वर्तमान मास्टर प्लान, 2021 - इस साल समाप्त हो रहा है।

मास्टर प्लान क्या है?

- किसी भी शहर का मास्टर प्लान शहर के नियोजकों और भू-स्वामी एजेंसी के विजन डॉक्युमेंट की तरह होता है, जो भविष्य के विकास को दिशा देता है।
- इसमें जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, आवास, परिवहन, सामुदायिक सुविधाओं और भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण, सिफारिशें और प्रस्ताव शामिल हैं।

'दिल्ली मास्टर प्लान- 2041' के मसौदे

- दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के मसौदे में दो खंड और 22 अध्याय शामिल हैं, जो वर्ष 2041 तक दिल्ली को स्थायी, रहने योग्य और जीवंत बनाने हेतु तैयार करना है।
- दिल्ली की नाइटलाइफ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। नाइट सर्किट के लिए जगह का चयन करना स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग और अन्य, संबंधित सामूहिक एजेंसियो का काम होगा। इसके तहत होटल. रेस्तरा समेत अन्य जगहों के बंद होने का समय बढ़ाया जाएगा।
- मास्टर प्लान में तीन प्रकार के सांस्कृतिक समूहों की पहचान की गयी है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करती है। इनमें शाहजहानाबाद के वालड सिटी और लुटियंस बंगला जोन (एलबीजेड), सांस्कृतिक परिसर और पुरातात्विक पार्क जैसे विरासत क्षेत्र शामिल हैं।

आवास क्षेत्र, पर्यावरण एवं पार्किंग पर जोर

- दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी को ध्यान में रखते हुए इस मसौदे में निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों को अधिक निवेश करने के लिए आमंत्रित करके, किराए के आवासों को प्रोत्साहित करने की चर्चा की गयी है।
- राष्ट्रीय राजधानी में आवास के लिए खाका निर्धारित करते हुए मसौदे में कहा गया है कि भविष्य में आवास जरूरतों को दिल्ली के 'ग्रीनफील्ड' क्षेत्रों में 'लैंड पूलिंग मॉडल' का उपयोग कर बड़े पैमाने पर विकास के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
- चिन्हित 'लैंड पूलिंग' क्षेत्रों में 17-20 लाख रिहायशी इकाइयां विकसित की जा सकती हैं। मसौदे में कहा गया है कि नगर के विकसित हिस्सों में जमीन की ऊंची कीमतों

को देखते हुए, यह विभिन्न आय समूहों के लिए उनके कार्यस्थलों के करीब आवास की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।

- पार्किंग की समस्याओं को दूर करने के लिए, मसौदे में सभी निजी मोटर वाहनों के उपयोगकर्ताओं को अधिकृत पार्किंग सुविधाओं, स्थानों और सड़कों के लिए भुगतान करना होगा।
- इस मसौदे का उद्देश्य प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से वाहनों के प्रदूषण को कम करना है। मसौदा में विभिन्न झीलों,प्राकृतिक नालियों और बावली का ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के निकट 'बफर जोन' की स्पष्ट सीमा निर्धारित की गई है। योजना के अनुसार नदी के किनारों पर, जहां भी संभव हो, 300 मीटर की चौड़ाई का 'बफर जोन' बनाया जाएगा।

महामारी के मद्देनजर बदलाव

- महामारी के कारण दुनिया में भारी बदलाव आया है, और बढ़ती आबादी ने बेरोजगारी में भारी वृद्धि की है। मास्टर प्लान 2041 का उद्देश्य आपात स्थिति में शरण स्थल, सामान्य रसोई और संगरोध स्थान प्रदान करने के लिए सामान्य सामुदायिक स्थान विकसित करना है।
- रात्री-कालीन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, सांस्कृतिक उत्सवों, बसों में मनोरंजन, मेट्रो, खेल सुविधाओं और खुदरा स्टोरों पर केंद्रित योजनाओं को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नाइट लाइफ सर्किट योजना में शामिल किया गया है।
- रात के समय की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, सांस्कृतिक उत्सवों, बस मनोरंजन, मेट्रो, खेल सुविधाओं और खुदरा स्टोर पर केंद्रित योजनाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नाइट लाइफ सर्किट योजना में शामिल किया गया है। यह यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम (mechanical ventilation systems) पर निर्भरता को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत कार्यक्षेत्रों, खुले क्षेत्रों के अनिवार्य निर्माण, बेहतर आवास डिजाइन और हरित-रेटेड विकास के माध्यम से महामारी के प्रति संवेदनशीलता को कम करने का भी प्रस्ताव करता है।

चुनौतियाँ

- कागज पर मास्टर प्लान शहर की प्रगति के लिए एक आदर्श दस्तावेज की तरह दिखता है। किन्तु जानकारों का मानना है कि जब कार्यान्वयन एजेंसियां इसे जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगी, तो उन्हें राजनीतिक टकराव, संसाधनों और धन की कमी व विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
- उदाहरण के लिए, भूतल पर पार्किंग बढ़ाने, कबाड़ वाहनों को हटाने, कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने, कचरा जलाने और कचरे को अलग करने की बात करने के बावजूद, इनमें से बहुत सी चीजें कभी लागू नहीं की जा सकीं।

6. शिक्षा मंत्रालय का ऑनलाइन मॉड्यूल

चर्चा का कारण

- हाल ही में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने स्कूल न जाने वाले बच्चों पर जानकारी संग्रहित करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया जो छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उम्र के अनुकूल स्कूलों में प्रवेश को सुगम बनाएगा।

प्रमुख बिन्दु

- शिक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि वर्तमान सत्र 2021-22 में पहली बार 16-18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा को मुक्त / दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से जारी रखा जा सके।
- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा चिह्नित स्कूल न जाने वाले बच्चों की जानकारी संग्रहित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है और इन आंकड़ों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ प्रबंध पोर्टल पर व्यवस्थित किया जाएगा।
- स्कूल न जाने वाले चिह्नित प्रत्येक बच्चे की और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी प्रखंड संसाधन समन्वय के तहत प्रखंड स्तर पर अपलोड होगी।
- नियमित स्कूलों में छह से 14 आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए उम्र के अनुकूल प्रवेश को सुगम बनाने के क्रम में 'समग्र शिक्षा' योजना में वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ताकि स्कूलों में उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने और शिक्षण में आए अंतर को पाटने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सके।

समग्र शिक्षा योजना

- भारत सरकार ने 2018-19 में समग्र शिक्षा-स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना लांच की थी। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
- इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में स्कूल की परिकल्पना निरंतरता के रूप में की गई है। पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक को स्कूल माना गया है और इसमें पहले की केंद्र की प्रायोजित योजनाएं -सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा शिक्षक शिक्षा (टीई)- शामिल हैं।
- वर्ष 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत किताबें, यूनिफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पहलों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए आज राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक खाई को पाटना है। योजना की पहुंच अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और बच्चों तक है। योजना में शहरी वंचित बच्चों, समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से प्रभावित बच्चों तथा दूरदराज और छिटपुट आबादियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान दिया गया है।

- समग्र शिक्षा योजना ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों को स्कूल अवसंरचना मजबूत बनाने में समर्थन देती है। योजना में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) द्वारा अंतर आधार पर निर्धारित वर्तमान स्कूलों की अवसंरचना को मजबूत बनाने का प्रावधान है। इसमें संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से मिले प्रस्ताव भी शामिल हैं। योजना में

वर्तमान स्कूल भवनों, शौचालयों तथा स्कूल अवसंरचना को उन्नत बनाए रखने के लिए अन्य सुविधाओं के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत का भी प्रावधान है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

7. महाराष्ट्र में पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा

चर्चा का कारण

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा देकर संरक्षित करने का फैसला किया है। इसके लिए महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम' 1975 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख संशोधन

- महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम में जो संशोधन होने हैं, उनमें हेरिटेज ट्री संकल्पना और उनके संरक्षण के पायलट प्रॉजेक्ट को शामिल करने, वृक्षों की उम्र, भरपाई वृक्षारोपण, बड़े पैमाने पर होने वाली पेड़ों की कटाई के लिए नियमों को सख्त बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना, प्राधिकरण की रचना, उसके कर्तव्य निश्चित किए जाने, पेड़ों की गिनती किए जाने, वृक्षारोपण के लिए सामूहिक जमीन निश्चित किए जाने, वृक्षों के पुनररोपण और संरक्षण के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढने, वृक्ष उपकर और दंड के प्रस्ताव को शामिल किए जाने आदि तत्वों का समावेश किया जाएगा।

'धरोहर वृक्ष' या 'हेरिटेज ट्री' क्या हैं?

- महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले पेड़ को हेरिटेज ट्री के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह विशिष्ट प्रजातियों से संबन्धित हो सकता है, जिसे समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

लाभ

- वृक्षों को हेरिटेज ट्री का दर्जा दिए जाने और भरपाई के लिए होने वाले वृक्षारोपण में वृक्षों की संख्या निश्चित करने के लिए वृक्षों की उम्र एक महत्वपूर्ण पैमाना होगा।
- वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 6 से 8 फुट के पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- जिस जगह पेड़ काटे गए हैं, उसी जगह या पौधे लगाने होंगे, यदि वहां जमीन उपलब्ध न हो, तो सार्वजनिक जमीन पर पौधारोपण किया जा सकेगा।
- वृक्षारोपण में लगाए गए वृक्षों का जियो टैगिंग कर अगले 7 वर्ष तक उनकी देखभाल करना आवश्यक होगा।
- यदि नुकसान भरपाई के रूप में होने वाला वृक्षारोपण संभव नहीं होगा, तो जो वृक्ष तोड़ा जा रहा है उस वृक्ष के मूल्यांकन से कम न हो, इतनी रकम जमा करानी होगी।

महाराष्ट्र ट्री अथारिटी

- वृक्षों के संरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र ट्री अथारिटी बनाने का भी निर्णय किया है।
- पांच वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले 200 से अधिक वृक्षों को काटने से पहले महाराष्ट्र ट्री अथारिटी से संपर्क करना होगा। महाराष्ट्र ट्री अथारिटी में लोकल ट्री अथारिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा जो स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के जानकार होंगे।
- ये ट्री अथारिटीज प्रति पांच वर्ष पर वृक्षों की गणना एवं उनका वर्गीकरण करवाएंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र 33 फीसद से कम न हो।

8. CHIME टेलीस्कोप एवं फास्ट रेडियो बर्स्ट

चर्चा का कारण

- हाल ही में कनाडा के हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट (CHIME) के सहयोग से पुणे स्थित 'टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च' (TIFR) और 'नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स' (NCRA) के शोधकर्त्ताओं ने 'फास्ट रेडियो बर्स्ट' (FRB) कैटालॉग का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया है।

फास्ट रेडियो बर्स्टस

- पहली बार (फास्ट रेडियो बर्स्टस) FRB साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पार्कस रेडियो टेलीस्कोप से पकड़ा गया था, तभी से उनके बारे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट जानना चाह रहे हैं। इसी साल 28 अप्रैल को कनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपैरिमेंट (CHIME) के वैज्ञानिकों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) को देखा था।
- ये बहुत ही चमकीली रेडियो तरंगें होती हैं जो कुछ ही मिलीसेंकंड में खत्म हो जाती हैं। ये संक्षिप्त और रहस्यमयी प्रकाश-दीप्तियाँ, ब्रह्मांड के विभिन्न और दूरस्थ हिस्सों के साथ-साथ हमारी अपनी आकाशगंगा में भी देखे जाती हैं।

CHIME परियोजना

- CHIME प्रोजेक्ट ने अब तक खोजे गए 'फास्ट रेडियो बर्स्ट' की संख्या को लगभग चौगुना कर दिया है। इस टेलीस्कोप ने वर्ष 2018 और 2019 के बीच अपने संचालन के पहले वर्ष में ही 535 नए FRBs का पता लगाया है। खगोलविदों को जल्द ही अधिक जानकारी के साथ FRBs की उत्पत्ति का पता लगाने की उम्मीद है।
- CHIME के आने से पहले, विभिन्न दूरबीनों ने मुट्ठी भर FRB देखे थे, लेकिन उनके अपने चयन मानदंड और सॉफ्टवेयर थे। लेकिन अब, CHIME की मदद से, हम चौबीसों घंटे आकाश के एक बड़े हिस्से का निरीक्षण कर सकते हैं और अभूतपूर्व दर पर FRBs का पता लगाने में सक्षम हुए हैं।
- यह ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में कनाडा की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल वेधशाला में स्थित है। पृथ्वी के परिघूर्णन के दौरान यह दूरबीन, आकाश के आधे भाग से प्रतिदिन रेडियो संकेत प्राप्त करती है।

9. संयुक्त राष्ट्र में 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च-स्तरीय संवाद'

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय संवाद' में संबोधन दिया है।

मुख्य बिन्दु

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद में अपना मुख्य संबोधन दिया है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया है।
- भूमि को जीवन और आजीविका का मूलभूत हिस्सा बताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने भूमि और उसके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को कम करने का आह्वान किया है।

सरकारी प्रयास

- भारत के प्रधानमंत्री ने भूमि क्षरण के मुद्दे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को प्रमुखता से रखने का बीड़ा उठाया है।
- दिल्ली घोषणापत्र-2019, भूमि तक बेहतर पहुंच और प्रबंधन का आह्वान करता है और लैंगिक रूप से संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर देता है।
- भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे संयुक्त वन क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई हो गया है।
- भारत, भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की राह पर है। इसके अलावा, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। यह 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करेगा।
- प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि कैसे भूमि की बहाली से मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका का एक अच्छा चक्र शुरू हो सकता है। उल्लेखनीय है कि बन्नी क्षेत्र में, घास के मैदानों को विकसित कर जमीन को बेहतर बनाया गया जिससे भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने में मदद मिली है। यह पशुपालन को बढ़ावा देकर चरवाहे संबंधी गतिविधियों और आजीविका में सहयोग करता है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना से, भारत कई विकासशील देशों को भूमि की बहाली के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता कर रहा है।
- प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा,

'मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि को हुए नुकसान को वापस पूर्व अवस्था में लाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ना हमारा पवित्र कर्तव्य है।'

पृथ्वी शिखर सम्मेलन (रियो) के बारे में

- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ।
- यह शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
- रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD), जैव विविधता पर समझौता (Convention on Biological Diversity- CBD) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) अस्तित्व में आए थे।

'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD)

- 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD), संयुक्त राष्ट्र के तीन रियो समझौतों में से एक है। भारत ने इससे संबंधित समझौते पर 14 अक्टूबर, 1994 को हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मरूस्थलीकरण से निपटना तथा सूखे या मरूस्थलीकरण से जूझ रहे देशों में इसके प्रभाव को कम करना है।

यूएनसीसीडी की 14वीं सीओपी

- यूएनसीसीडी की 14वीं सीओपी में दिल्ली घोषणापत्र-2019 को स्वीकार किया गया था। यह सीओपी वर्ष 2019 में भारत में हुई थी।इस सीओपी में भूमि की गुणवत्ता बहाली, सूखा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और पानी की कमी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई थी।

10. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रीय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल' लॉन्च किया गया है, इसका नाम "ai-gov-in" है। इसके अलावा 28 मई, 2021 को 'राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल' (National AI Portal) ने अपनी पहली वर्षगाँठ मनाई।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल' के बारे में

- भारत का राष्ट्रीय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल' इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा।
- पोर्टल एआई से संबंधित आर्टिकल्स, निवेश फंडों, एआई, स्टार्टअप्स, कंपनियों, संसाधनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे एआई से संबंधित संसाधनों को साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा और इसलिए भारत में AI से संबंधित विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के उद्देश्य

- यह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित आर्टिकल, स्टार्टअप्स, AI में निवेश फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों आदि को शेयर करेगा। यह पोर्टल दस्तावेजों, केस स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट आदि को भी शेयर करेगा।
- इस पोर्टल को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और IT उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्सस और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नास्कॉम) मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है?

- कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय किसी कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन द्वारा मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है, जिसमें उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से मनुष्यों के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता आदि शामिल है।
- AI में जटिल चीजें शामिल होती हैं जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। AI का उपयोग वित्त और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न उद्योगों में किया जा रहा है।
- फर्मों का एक वैश्विक नेटवर्क (PwC) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने AI के उपयोग में 45% की वृद्धि दर्ज की, जो कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद सभी देशों में सबसे अधिक है।

भारत में AI के उदाहरण

- कोविड-19 के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिये कृत्रिम बौद्धिकता आधारित प्लेटफार्म का सहारा लिया जायेगा। इसके तहत छाती का एक्स-रे करके उसे डॉक्टरों के पास व्हॉट्स-एप्प के जरिये भेज दिया जायेगा।

डॉक्टर उसे एक्स-रे मशीन पर देख सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम एक्स-रे सेतु रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में कोविड की जांच और कार्रवाई के हवाले से इससे आसानी और तेजी से काम हो सकता है।

- MyGov द्वारा संचार सुनिश्चित करने के लिये AI- सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था।
- AI आधारित पोर्टल 'SUPACE' का उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता करना है।
- ICRISAT ने एक AI-पावर बुवाई एप विकसित किया है, जो स्थानीय फसल की उपज और वर्षा पर मौसम के मॉडल तथा डेटा का उपयोग करता है एवं स्थानीय किसानों को यह सलाह देता है कि उन्हें अपने बीज कब बोने चाहिये।
- बिहार में लागू किया गया AI-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल अब पूरे भारत को कवर करने के लिये विस्तारित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगभग 200 मिलियन लोगों को आसन्न बाढ़ जोखिम के बारे में 48 घंटे पहले अलर्ट और चेतावनी प्रदान की जा सके।
- भारत में कुछ बैंकों ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और जोखिम प्रबंधन में एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ाने हेतु AI को अपनाया है।

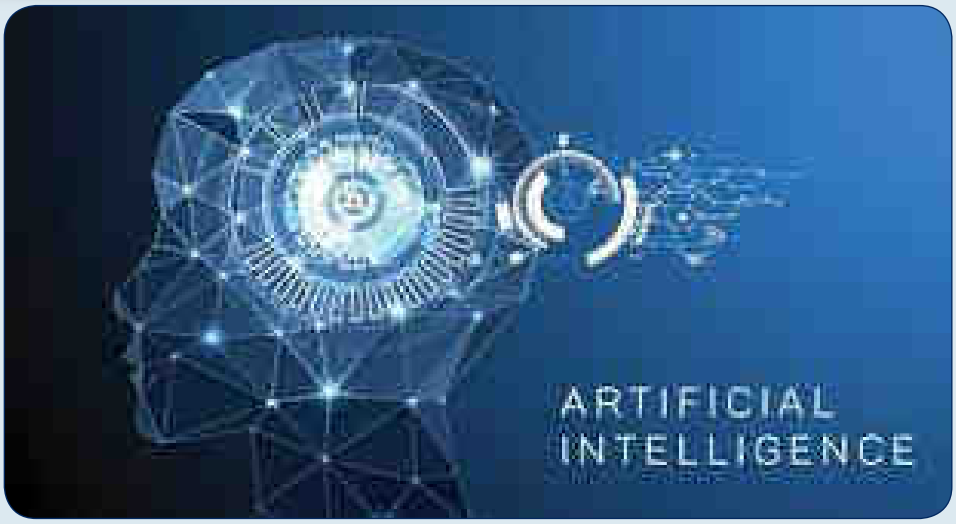

11. नागालैंड में नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन

चर्चा का कारण

- हाल ही में नागालैंड सरकार ने केंद्र के साथ नागा शांति समझौते और राजनीतिक मुद्दों के समाधान लिए विपक्षी नेताओं की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नेफियू रियो करेंगे।

प्रमुख घटनाक्रम

- नागा वार्ता 2020 की शुरुआत से गतिरोध पर है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-(इसाक मुइवा) (एनएससीएन-आईएम) के नेता टी. मुइवा ने प्रमुख वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि के साथ कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया था।
- दोनों के बीच संचार के टूटने की विफलता के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएससीएन-आईएम के साथ चर्चा जारी रखने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम को प्रतिनियुक्त किया।
- यह आर.एन. रवि ही थे जिन्होंने 3 अगस्त, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्र की ओर से एनएससीएन-आईएम के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- गौरतलब है कि एनएससीएन-आईएम नागाओं के लिए एक अलग संविधान, ध्वज और असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में बसे हुए सभी नगा क्षेत्रों को आत्मसात करने की मांग कर रहा है।

वर्तमान स्थिति

- भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/एनके (एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफॉर्मेशन (एनएससीएन/आर) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/के-खांगो (एनएससीएन/के-खांगो) के बीच संघर्ष विराम समझौते जारी हैं।
- एनएससीएन-के ने केंद्र के साथ 2001 में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2015 में इसने समझौते को एकतरफा रूप से तोड़ दिया था। उस समय समूह के तत्कालीन अध्यक्ष एसएस खापलांग जीवित थे।
- इसके बाद पिछले साल दिसंबर में एनएससीएन-के ने खूंखार उग्रवादी निकी सुमी के नेतृत्व में संघर्ष विराम की घोषणा की थी और कहा था कि संगठन ने शांति वार्ता शुरू करने के लिए केंद्र से संपर्क किया है।
- सबसे बड़े नगा संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम-इसाक मुइवाह (एनएससीएन-आईएम) ने केंद्र सरकार के साथ 1997 में संघर्ष विराम समझौता किया था और वह तभी से शांति वार्ताओं में शामिल रहा है. हाल ही में आए तनाव के बीच एनएससीएन-आईएम के प्रमुख टी. मुइवाह ने जोर देकर कहा था कि नगा कभी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही वे भारतीय संविधान को स्वीकार करेंगे।
- इस संगठन ने नगा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए तीन अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 'फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 18 साल तक चली 80 से अधिक दौर की वार्ता के बाद हुआ था। हालांकि, वर्तमान में एनएससीएन-आईएम के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध कायम है, क्योंकि एनएससीएन (आई-एम) शुरू से ही असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागा-बहुल इलाकों को मिला कर नागालिम यानी ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग करता रहा है, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया है।

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 'बीड मॉडल'

चर्चा का कारण

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बीड मॉडल के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिये प्रयास शुरू कर दिया है।

बीड मॉडल क्या है?

- महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित, बीड जिला किसी भी बीमा कंपनी के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इसकी वजह यह है कि यहां के किसान बार-बार बारिश नहीं होने या भारी बारिश के कारण अपनी फसल गंवा देते हैं।
- ऐसे में उच्च भुगतान को देखते हुए बीमा कंपनियों को निरंतर घाटा हुआ है। राज्य सरकार को बीड में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी।

इस समस्या का समाधान

- बीमा कंपनियों के नुकसान को देखते हुए राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके अनुसार बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम राशि के 110% तक की सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि मुआवजा की राशि, बीमा कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा से अधिक हो जाती है, तो इस अतरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- यदि मुआवजा के रूप में दी गई राशि, एकत्रित प्रीमियम से कम रहती है, तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% हैंडलिंग या प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रख लेगी और शेष राशि राज्य सरकार (प्रीमियम अधिशेष) को प्रतिपूर्ति करेगी।

बीड मॉडल को लागू करने का कारण

- बीड मॉडल में बीमा कंपनी के लाभ में कमी आने की उम्मीद है और राज्य सरकार को धन के दूसरे स्रोत तक पहुँच प्राप्त होगी।
- प्रतिपूर्ति की गई राशि से अगले वर्ष के लिए राज्य द्वारा फसल-नुकसान होने वाले किसी भी वर्ष की अवधि में अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने में मदद मिल सकती है।

चुनौतियाँ

- हालांकि किसानों के लिए इस मॉडल का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए इस मॉडल के लागू होने की संभावना कम नजर आ रही है। इस पर सवाल बने हुए हैं कि राज्य सरकार अतिरिक्त राशि कैसे जुटाने जा रही है, और प्रतिपूर्ति की गई राशि को कैसे प्रशासित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया गया।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है।
- फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया जाता है। कारोबारी और बागबानी फसलों पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। इन फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है।
- खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना के तहत केवल दो प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम होता है। शेष राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- यह एक केंद्रीय योजना है तथा राज्य के कृषि विभागों द्वारा, केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

13. ऑपरेशन ओलिविया

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley Turtles) की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया (Operation Olivia) शुरू किया है।

ऑपरेशन ओलिविया क्या है?

- ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था।
- यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।
- कानूनों को लागू करने के लिये तटरक्षक बल की संपत्ति जैसे- तेज गश्ती जहाजों, एयर कुशन जहाजों, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और डोर्नियर विमान का उपयोग करते हुए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।
- यह ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है जब वे नवंबर से दिसंबर के महीनों में प्रजनन के लिए ओडिशा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं।
- इसके तहत तटरक्षक बल की संपत्ति जैसे फास्ट पेट्रोल वेसल, इंटरसेप्टर क्राफ्ट, एयर कुशन वेसल और डोर्नियर एयरक्राफ्ट के जरिए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।
- नवंबर 2020 से मई 2021 के बीच, तटरक्षक बल ने 225 जहाज दिवस और 388 विमान घंटे समर्पित किए हैं। उन्होंने 3.49 लाख कछुओं की रक्षा की है।

ओलिव रिडले के बारे में

- ओलिव रिडले कछुओं को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची के तहत असुरक्षित (vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

की अनुसूची- 1 में शामिल किया गया है।

- वे लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन (CITES के परिशिष्ट- 1 में भी सूचीबद्ध हैं।
- उनके सामूहिक घोंसले को अरिबाडा (Arribada) कहा जाता है।
- गहिरमाथा, अस्टारंगा तट, देवी नदी का मुहाना और रुशिकुल्या भारत में ओडिशा तट से 4 अरिबाडा स्थल हैं।
- ओलिव रिडले कछुए मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
- ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।

चिंताएँ

- इन कछुओं का शिकार मांस, खाल, चमड़े और अंडे के लिये किया जाता है।
- इनको सबसे गंभीर खतरा घोंसले का नुकसान, संभोग के मौसम के दौरान समुद्र तटों के आसपास अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने के कारण ट्रॉल नेट और गिल नेट में उलझने से उनकी आकस्मिक मौत है।
- प्लास्टिक, मछली पकड़ने के जाल, पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए अन्य कचरे का बढ़ता मलबा।

14. पासिफए (PASIPHAE) परियोजना

चर्चा का कारण

- 'पोलर-एरियाज स्टेलर-इमेजिंग इन पोलेराइजेशन हाई-एक्यूरेसी एक्सपेरीमेंट' (PASIPHAE) अर्थात 'पासिफए' एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या ध्रुवण (Polarisation) का अध्ययन करना है।

PASIPHAE परियोजना क्या है?

- PASIPHAE से तात्पर्य पोलराइजेशन हाई-एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट में पोलर-एरिया स्टेलर-इमेजिंग है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है।
- वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है।
- यह नाम ग्रीक सन गॉड हेलिओस की बेटी पासीफे से प्रेरित है।
- सर्वेक्षण उत्तरी और दक्षिणी आसमान को एक साथ देखने के लिए दो उच्च तकनीक वाले ऑप्टिकल पोलीमीटर का उपयोग करेगा।
- सर्वेक्षण में, काफी धुंधले तारों से निकलने वाले प्रकाश के ध्रवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये तारे बहुत अधिक दूरी पर स्थित है और अभी तक इनके ध्रुवीकरण संकेतों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया गया है।
- अध्ययन से प्राप्त इन आंकड़ों का संयोजन करके, खगोलविद WALOP (वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलारिमीटर) नामक एक अत्याधुनिक पोलरिमीटर उपकरण के द्वारा विस्तृत आकाश क्षेत्रों के अंतर-तारकीय माध्यम की पहली चुंबकीय क्षेत्र टोमोग्राफी मैपिंग (magnetic field tomography mapping) करेंगे।
- इन तारों की दूरी GAIA उपग्रह द्वारा की गई माप से ज्ञात की जाएगी।

परियोजना की आवश्यकता क्यों?

- जैसा कि ब्रह्मांड को भरने वाले ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि (सीएमबी) विकिरण की उपस्थिति से प्रमाणित है। लगभग 14 अरब साल पहले अपने जन्म के बाद से, ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है।
- अपने जन्म के तुरंत बाद, ब्रह्मांड एक छोटी ज्वलनशील चरण के माध्यम बहुत उच्च दर से विस्तारित हुआ। हालाँकि, अब तक, प्रारंभिक ब्रह्मांड से जुड़े विस्तार के केवल सिद्धांत और अप्रत्यक्ष प्रमाण ही रहे हैं।
- विस्तार के चरण का एक निश्चित परिणाम यह है कि सीएमबी विकिरण के एक छोटे से अंश में एक विशिष्ट प्रकार के ध्रुवीकरण (वैज्ञानिक रूप से बी-मोड सिग्नल के रूप में जाना जाता है) के रूप में इसकी छाप होनी चाहिए।
- इस संकेत का पता लगाने के पिछले सभी प्रयास मुख्य रूप से हमारी आकाशगंगा, द्वारा उत्पन्न कठिनाई के कारण विफल हुए, जो ध्रुवीकृत विकिरण की प्रचुर मात्रा में उत्सर्जन करता है।
- इसके अलावा, इसमें ढेर सारे धूल के बादल होते हैं जो गुच्छों के रूप में मौजूद होते हैं।
- जब इन धूल के बादलों से तारों का प्रकाश गुजरता है, तो वे बिखर जाते हैं और ध्रुवीकृत हो जाते हैं।
- ध्रुवीकरण, प्रकाश का एक गुण होता है, जो प्रकाश तरंग के दोलन करने की दिशा को दर्शाता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड के तीव्र स्फीतिकारी चरण के दौरान उत्सर्जित CMB विकिरण के एक अल्पांश के चिह्न एक विशिष्ट प्रकार के ध्रुवीकरण पर मिलने चाहिए, इस ध्रवीकरण को तकनीकी रूप से बी-मोड सिग्नल के रूप में जाना जाता है।
- इन बी-मोड सिग्नलों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड-स्फीति के दौरान देखी जाने वाली शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के परिणामस्वरूप मानी जाती है।
- हमारी अपनी आकाशगंगा में पाए जाने वाले धूल के विस्तृत बादलों के कारण, इसमें मौजूद भारी मात्रा में ध्रुवीकृत विकिरण और इन संकेतों को अलग करना मुश्किल हो जाता है।
- संक्षेप में, PASIPHAE प्रोजेक्ट के तहत इन बाधसाओं के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अंतत: हम ब्रह्मांड की शुरुआत में घटित घटनाओं के बारे में जान सकें।

15. शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन

चर्चा का कारण

- हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने शुक्र ग्रह के लिये एक नए एनविजन मिशन (EnVision mission) की घोषणा की है।

प्रमुख बिन्दु

- इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) का भी योगदान होगा।
- इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किये जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस अंतरिक्षयान को शुक्र तक पहुँचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा पूरी करने में 16 महीने और लगेंगे।
- अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के साथ साथ इसके वातावरण में पायी जाने वाली गैसों की निगरानी करेगा । इसके अतिरिक्त इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को ले जाएगा।
- नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा। एनविजन मिशन शुक्र ग्रह के लिये ESA के नेतृत्व वाले वीनस एक्सप्रेस (2005-2014) नामक दूसरे मिशन का अनुसरण करेगा जो वायुमंडलीय अनुसंधान पर केंद्रित है और ग्रह की सतह पर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट के बारे में पता करेगा।

शुक्र ग्रह के लिए अन्य मिशन

- जापान का अकात्सुकी अंतरिक्ष यान भी 2015 से शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। अकात्सुकी के जरिए ही हम जान पाए कि ग्रह को तेज हवाएं अशांत बनाए रखती हैं, इन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंग माना गया है।
- हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दो नए रोबोटिक मिशन - डाविंसी प्लस (DAVINCI$) और वेरिटास (VERITAS) की घोषणा की है। ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2028 से 2030 के बीच शुरू किए जाएंगे।
- आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), शुक्र ग्रह (Venus Planet) पर शुक्रयान (Shukrayaan) मिशन भेजेगा, ताकि इस गृह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। इस मिशन के भविष्य में 2024 या 2026 में लॉन्च की स्थिति बन सकती है। शुक्रयान (Shukrayaan) मिशन में रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी आदि देशों का 'सहयोगी योगदान' (collaborative contributions) शामिल है।
- शुक्र ग्रह के लिए सोवियत संघ द्वारा विकसित पहला अंतरिक्ष यान वेनेरा सीरीज' (Venera series) का था। हालांकि ग्रह की कठोर परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक यह यान जीवित नहीं रह सका। इसके बाद नासा के मैगलन (Magellan) मिशन (1990-1994) ने शुक्र ग्रह का अध्ययन किया।

शुक्र ग्रह का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों?

- वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हैं और संभावना है कि जीवन इसके बादलों की ऊपरी परतों में मौजूद हो सकता है जहां तापमान कम होता है। गौरतलब है कि नासा का 'दविंची+' शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करेगा। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या शुक्र पर कोई समुद्र भी था?
- इसके अतिरिक्त वेरिटास, शुक्र की सतह पर कठोर चट्टान के नमूने प्राप्त करके इस पड़ोसी ग्रह के भूवैज्ञानिक विज्ञान को समझने में मदद करेगा। इसके जरिए यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह ग्रह कैसे बना?
- एनविजन मिशन से भी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे शुक्र ग्रह एक भट्टी जैसी दुनिया बन गया, जिसकी सतह सीसा को पिघलाने में सक्षम है।
- शुक्र ग्रह का इतिहास, ग्रीनहाउस प्रभाव को पढ़ने और धरती पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यह समझने का बेहतरीन मौका उपलब्ध कराएगा। इसके लिए ऐसे मॉडलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें शुक्र के वायुमंडल की चरम स्थितियों को तैयार किया जा सकता है और परिणामों की तुलना धरती पर मौजूदा स्थितियों से कर सकते हैं।
- वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन (केवल जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित एक रसायन) की उपस्थिति का पता लगाया। इससे वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह पैदा हो गया था कि इस ग्रह पर जीवन के कुछ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शुक्र के उच्च तापमान और उसके अम्लीय वातावरण को देखते हुए इस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव है। फिर भी इस खोज से यह पता चल सकता है कि क्या शुक्र पर जीवन था?

शुक्र ग्रह

- शुक्र चंद्रमा के बाद आकाश में दूसरा सबसे चमकीला पिंड है। यह अपने घने बादलों के कारण चमकीला दिखाई देता है जो प्रकाश को परावर्तित और बिखेरता है। समान आकार और संरचना के कारण शुक्र को अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है. शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं।
- शुक्र ग्रह पर कार्बन खिसककर वातावरण में चला गया है जिससे इसके वातावरण में तकरीबन 96 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड है। इससे बहुत ही तेज ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न हुआ जिससे सतह का तापमान 750 केल्विन (470 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री फॉरेनहाइट) तक चला गया है।
- यहां का अधिकतम तापमान 90 बार जितने उच्च दबाव जितना है (तकरीबन एक किलोमीटर नीचे के पानी के प्रवाह जितना)। यह दबाव इतना है जो तत्काल अधिकांश लैंडरों को नष्ट कर सकता है। शुक्र तक अब तक गए मिशन योजना के मुताबिक नहीं रहे हैं।
- शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि यह पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है। शुक्र के पास न तो चंद्रमा है और न ही छल्ले।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

मेघा राजगोपालन

नफताली बेनेट

प्रोफेसर राधा मोहन

राम प्रसाद बिस्मिल

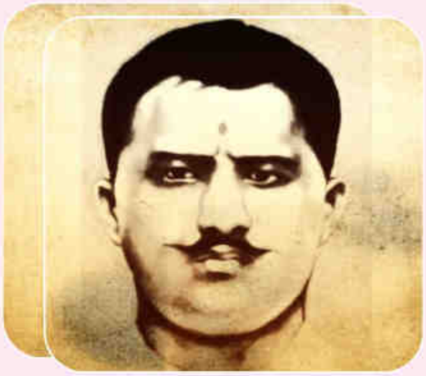

सुंदर पिचाई

आंग सान सू की

सलमान रुश्दी

1. मेघा राजगोपालन

- भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मेघा राजगोपालन ने दुनिया के सामने चीन के झूठ की पोल खोली है। मेघा ने अपनी रिपोर्ट्स में चीन के डिटेंशन कैंपों में लोगों को दी जा रही यातना की सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगुर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है।
- मेघा राजगोपालन के साथ इंटरनेट मीडिया बजफीड न्यूज के दो बड़े पत्रकारों को भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने फ्लोरिडा में सरकारी अधिकारियों के बच्चों की तस्करी को लेकर टंपा बे टाइम्स के लिए इंवेस्टीगेशन स्टोरी की थी। उन्होंने इस स्टोरी के जरिए कई अहम खुलासे किए थे।

पुलित्जर पुरस्कार

- पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसे अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और 'पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड' द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- 'पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड' का निर्माण कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा होता है।
- यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिये अपनी वसीयत से पैसा दिया था। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 'सार्वजनिक सेवा श्रेणी' में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक भी दिया जाता है।

2. नफताली बेनेट

- इजराइल में 12 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाते हुए 49 वर्षीय नफताली बेनेट (Naftali Bennett) ने इजराइल के प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली है।

कौन हैं नफताली बेनेट?

- 49 वर्षीय बेनेट राजनीतिक में आने से पहले टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो, बेनेट अमेरिका में जन्मे माता-पिता के बेटे हैं। बेनेट को अर्थव्यवस्था पर अति-उदार माना जाता है और वह ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं।
- बेनेट ने साल 2005 में अपने टेक स्टार्टअप को 145 मिलियन डॉलर में बेचने के बाद राजनीति में कदम रखा, और अगले साल वह नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, जो उस समय विपक्ष में थे। बेनेट ने 2006 और 2008 के बीच नेतन्याहू के लिए वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया। हालांकि, नेतन्याहू के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी छोड़ दी। नेतन्याहू का साथ छोड़ने के बाद, बेनेट 2010 में येशा काउंसिल के प्रमुख बने, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के बसने की लॉबी करती है। 2012 में बेनेट ने धुर दक्षिणपंथी ज्यूइश होम पार्टी की कमान संभाली थी।

इजराइल

- इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिणपूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनॉन, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र है। मध्यपूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सन् 1948 में आधुनिक इसरायल राष्ट्र की स्थापना हुई। यरूशलम इसरायल की राजधानी है पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है, जो दाएँ से बाँए लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इसरायली या इजरायली कहा जाता है।

3. प्रोफेसर राधा मोहन

- हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी को जैविक तकनीकों का उपयोग करके बंजर भूमि के एक टुकड़े को दुर्लभ उपज वाले एक विशाल जंगल के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है।

राधा मोहन

- 1943 में नयागढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुए राधा मोहन ने पुरी के एससीएस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया और 1965 में उत्कल यूनिवर्सिटी से एप्लाइड इकोनॉमिक्स में पीजी किया। पुरी में एससीएस कॉलेज के प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें प्रदेश का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ओडिशा सरकार ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें उत्कल सेवा सम्मान दिया। इसी तरह यूएनईपी ने उन्हें द ग्लोबल रोल ऑफ

ऑनर प्रदान किया। राधामोहन को 2020 में कृषि में उनके काम के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

4. राम प्रसाद बिस्मिल

- हाल ही में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती मनाई गई।
- राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रान्तिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फाँसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यन्त्र व काकोरी-काण्ड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस (उपनाम) था जिसका हिन्दी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कवितायें लिखते थे।
- उनका जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के घर हुआ था। उनका मानना था कि हिंसा और रक्तपात के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसका अर्थ था कि उनके विचार महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्शों क विपरीत थे। 19 दिसंबर, 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फाँसी दी गई।

काकोरी काण्ड

- काकोरी काण्ड उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित यह स्थान आधुनिक भारत में चर्चा का विषय बना। 9 अगस्त, 1925 को इस स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जाई जा रही संग्रहीत धनराशि को लूटा। यह घटना इतिहास में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत यह कार्य करने की योजना बनाई। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोंक पर काबू कर लिया। गार्ड

के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल चार हजार रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाकउल्ला, चन्द्रशेखर आजाद, राजेन्द्र लाहिड़ी, सचीन्द्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशनसिंह को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। सचीन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ और मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्षों का सश्रम कारावास दिया गया। कुछ समय बाद अशफाकउल्ला को मृत्युदण्ड दिया गया।

5. सुंदर पिचाई

- हाल ही में भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, ने कहा कि कंपनी आईटी संबंधित सभी नियमों का पालन करने के लिए भारत सरकार के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सुंदर पिचाई का मूल नाम पिचाई सुंदराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। हालांकि, ट्विटर पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका जन्म 12 जुलाई को हुआ था। सुंदर पिचई गूगल की पैरेंट कंपनी एल्फाबेट (Alphabet) के भी प्रमुख बन गए हैं। पिचाई ने अपनी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से की, उसके बाद वारटन बिजनस

स्कूल से एमबीए किया। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है।

सुंदर पिचाई की प्रमुख सफलता

- सुंदर पिचाई ने गूगल के सह-संस्थापकों, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को आश्वस्त किया कि गूगल स्वयं का एक ऐसा ब्राउजर लांच करे जो कि यूजर फ्रेंडली हो। सुन्दर के प्रयासों के कारण अंततः 2008 में गूगल के ब्राउजर 'क्रोम' को लांच कर दिया गया था।
- यह ब्राउजर बहुत सफल साबित हुआ और फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए, क्रोम दुनिया में नंबर 1 ब्राउजर बन गया। पिचाई की इस पहल ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्द और वे गूगल में एक जाना-माना नाम हो गये थे।

6. आंग सान सू की

- आंग सान सू की म्यांमार (बर्मा) की एक राजनेता, राजनयिक तथा लेखक हैं। वे बर्मा के राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री हैं जिनकी 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गयी थी। सू की ने बर्मा में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए लम्बा संघर्ष किया। मानवाधिकारों की पैरोकार मानी जाने वाली सू की को साल 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- आंग सान सू की का जन्म म्यांमार के रंगून में हुआ। वह जब दो साल की थीं तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। सू की ने 1960 तक बर्मा में पढ़ाई की लेकिन इसके बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गईं। 1988 में वह एक बार फिर म्यांमार लौटीं जहां सेना का अत्याचार जारी था। इसके बाद सू की ने देश में मानवाधिकार हनन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सू की ने जनवरी 2012 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अप्रैल में हुए चुनावों में उन्होंने आसानी से जीत हासिल की और 2 मई को उन्होंने शपथ ली थी।

7. सलमान रुश्दी

- सर अहमद सलमान रुश्दी (जन्म 19 जून 1947) एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन (1981) से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला। उनके अधिकांश प्रारंभिक उपन्यास भारतीय उप-महाद्वीप पर आधारित हैं। उनकी शैली का वर्गीकरण अक्सर ऐतिहासिक कल्पना के साथ संयोजित जादुई यथार्थवाद के रूप में किया जाता है और उनकी कृतियों की प्रमुख विषय-वस्तु, पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच कई रिश्तों के जुड़ने, अलग होने और देशांतरणों की कहानी रही है।
- उनका चौथा उपन्यास सेटेनिक वर्सेज (1988), विवाद के केंद्र में था, जिसकी मुसलमानों सहित कई देशों में इसका विरोध हुआ।
- भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून, 1947 को मुंबई में हुआ था। सलमान ने अपना पहला उपन्यास 'ग्राइमल' साल 1975 में लिखा था, जिसे ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। लेकिन उनके अगले उपन्यास 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' (1981) ने उन्हें रातों-रात प्रसिद्धि दिला दी। रुश्दी की इस किताब को पिछले 100 सालों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक माना गया था। इसके लिए उन्हें 1981 में ही बुकर सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने 'शेम' (1983), 'द जगुआर स्माइल' (1987), 'द सैटेनिक वर्सेज' (1988), 'ईस्ट-वेस्ट' (1994), 'द मूर्स लास्ट साई' (1995), 'द ग्राउंड बिनीथ हर फीट' (1999), 'शालीमार द क्राउन' (2005) जैसी प्रमुख और बेहतरीन रचनाएं लिखीं, जिनके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित स्थान

श्रीशैलम मंदिर

उमलिंग ला

न्यू अटलांटिक चार्टर

पक्के बाघ अभयारण्य

अंडमान और निकोबार में
मिला कॉफी परिवार का पेड़

1. श्रीशैलम मंदिर

- हाल ही में श्रीशैलम मंदिर परिसर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र मिले हैं। श्रीशैलम में मिले ताम्रपत्र 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के हो सकते हैं। शिलालेखों के 6 सेटों में से 4 शिलालेख संस्कृत और नंदी-नागरी लिपि में हैं और अन्य दो प्लेटें तेलुगु लिपि में हैं।

श्रीशैलम देवस्थानम

- श्रीशैलम (श्री सैलम नाम से भी जाना जाता है) नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्री सैलम पहाडी पर स्थित है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इस कारण यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में श्री शैल काण्ड नाम का अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गायी है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने

जब इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। श्री शैलम का सन्दर्भ प्राचीन हिन्दू पुराणों और महाभारत में भी आता है।

2. उमलिंग ला

- जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित 'उमलिंग ला' (Umling La) विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। यह समुद्र तल से 5.793 मीटर (19,005 फीट) की ऊंचाई पर है। उमलिंग ला दर्रे से गुजरने वाली 54 किमी लंबी यह सड़क 'चिसुमले' (Chisumle) को डेमछोक (Demchok) गांव से जोड़ती है।
- इस सड़क परियोजना का निर्माण 'प्रोजेक्टहिमांक' के तहत 'सीमा सड़क संगठन' (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा है।

सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organization- BRO)

- सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूमिस्खलन तथा चट्टानों के गिरते-टूटते रहने से सड़कें टूटती रहती हैं। इनको सुचारु बनाये रखने के लिये संगठन

को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी।

3. न्यू अटलांटिक चार्टर

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने हाल ही में कॉर्नवाल में बैठक की और अटलांटिक चार्टर से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया और "न्यू अटलांटिक चार्टर" (New Atlantic Charter) नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

न्यू अटलांटिक चार्टर (New Atlantic Charter) क्या है?

- न्यू अटलांटिक चार्टर नामक एक समझौते पर 10 जून, 2021 को बोरिस जॉनसन और जो बाईडेन के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह 1941 के अटलांटिक चार्टर का एक नया संस्करण है। पश्चिमी गठबंधन को फिर से परिभाषित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

अटलांटिक चार्टर

- अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी एक महत्वपूर्ण नीति वक्तव्य था, जिसने दुनिया के

लिए सहयोगी लक्ष्यों को परिभाषित किया था। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका

के नेताओं ने काम का मसौदा तैयार किया और द्वितीय विश्व युद्ध के सभी सहयोगियों ने बाद में इसकी पुष्टि की। चार्टर ने युद्ध के आदर्श लक्ष्यों को बताया- कोई क्षेत्रीय उन्नति नहीं; लोगों की इच्छाओं के खिलाफ कोई क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं, आत्मनिर्भरता; स्वयं से वंचित लोगों को स्व-सरकार की बहाली; व्यापार प्रतिबंधों में कमी; सभी के लिए बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक सहयोग; डर से स्वतंत्रता; समुद्र की स्वतंत्रता; और बल के उपयोग के साथ-साथ आक्रामक राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण। अटलांटिक चार्टर के अनुयायियों ने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो आधुनिक संयुक्त राष्ट्रों का आधार बन गया।

- अटलांटिक चार्टर ने बाद के विश्व के लिए लक्ष्य निर्धारित किए और उसके बाद दुनिया को आकार देने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रेरित किया। टैरिफ और व्यापार (जीएटीटी) पर सामान्य समझौता, यूरोपीय उपनिवेशों के बाद की आजादी, और बहुत कुछ अटलांटिक चार्टर से लिया गया है।

न्यू अटलांटिक चार्टर के उद्देश्य

- लोकतंत्र के सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करने और संस्थानों को मजबूत और अनुकूलित करने के उद्देश्य से न्यू अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह चार्टर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों पर एकजुट करने का प्रयास करता है। यह साइबर खतरों के खिलाफ भी सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा। यह सभी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता देता है।

4. पक्के बाघ अभयारण्य

- पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है तथा लगभग 862 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह खेलांग वन प्रभाग का एक हिस्सा था तथा इसे 1977 में एक खेल अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। बाद में 2002 में इसे एक टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया।
- यह बाघ अभयारण्य अरूणाचल प्रदेश में वन्य जीवों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए वन अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। रिजर्व के जंगल में बाघों के बेहतर रख-रखाव के अलावा भी कई अन्य जानवरों की प्रजातियां जैसे फिशिंग कैट, सियार, जंगली भैंसें, फ्लाइंग स्क्वैरल (गिलहरी), क्लाउडेड तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सांभर, हाथी, पांडा, रीसस मकाक बंदर, हिरण और जंगली सुअर आदि भी मौजूद हैं।

5. अंडमान और निकोबार में मिला कॉफी परिवार का पेड़

- हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में 'पाइरोस्ट्रिया लालजी' (Pyrostria Lalgi) का एक 15 मीटर लंबा पेड़ खोजा गया है जो कॉफी परिवार के वंश से संबन्धित है। यह दक्षिण अंडमान में वंदूर जंगल मे पाया गया। नई प्रजाति 'पाइरोस्ट्रिया लालजी' (Pyrostria laljii), भारत में पायरोस्ट्रिया वंश का पहला रिकॉर्ड भी है। ध्यातव्य है कि इन प्रजातियों के पेड़ आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं।
- इस जाति के पेड़ के तने लंबे होते है तथा इसके तने पर एक सफेद रंग की कोटिंग होती है। इसके आयताकार-आकृति वाले नुकीले पत्ते होते हैं। ध्यातव्य है कि 'पायरोस्ट्रिया लालजी' आईयूसीएन स्थिति के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति का है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिन्द महासागर में स्थित है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
- अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। दो प्रमुख द्वीपसमूहों से मिलकर बने इस द्वीपसमूह को 10° m अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इस द्वीपसमूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

ऑटिस्टिक प्राइड दिवस

विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस

अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस

अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिजम जागरूकता दिवस

विश्व शरणार्थी दिवस

विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

1. ऑटिस्टिक प्राइड दिवस

- लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे (Autistic Pride Day) मनाया जाता है। इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों की अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार ब्राजील में 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की मानें तो हर 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। जिनमें से लगभग 40% ऑटिस्टिक बच्चे बोलने में सक्षम नहीं होते हैं।

ऑटिज्म क्या है? (What is Autism?)

- यह एक विकासात्मक विकार है जिसमे प्रभावित व्यक्ति सामाजिक संपर्क और संचार की कठिनाइयों का सामना करता है। अर्थात् इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से दूर रहना चाहता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को प्राय: मानवाधिकारों के उल्लंघन, भेदभाव और तमाम तरह की गलत धारणाओं का सामना करा पड़ता है। ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर बच्चे के पहले तीन वर्षों के दौरान पहचाने जाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं। यह विकार आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से जुड़ा हुआ है। नीले रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। 2015 तक दुनिया भर में ऑटिज्म से लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित थे। यह विकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है।

2. विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से लड़ने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र का यह दिन हरे पेड़ पौधे, संधारणीय विकास, मानवजाति के स्वास्थ्य के साथ पृथ्वी के भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर उन स्थितियों को खत्म होने से बचाना है जहां मानव और अन्य जानवर अपना जीवन जी सकें। विदित हो कि मरुस्थलीकरण और सूखे जैसे हालात ना केवल मानवीय जीवन को कठिन बना रहे हैं। बल्कि पर्यावरण को ऐसे हालात की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी असंभव है।

विश्व मरुस्थलीकरण (रेगिस्तांन) रोकथाम दिवस (डब्ल्यूडीसीडी) का इतिहास

- वर्ष 1995 से विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस (डब्ल्यूडीसीडी) से प्रत्येक साल विश्व के विभिन्न देशो में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरुकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव ए/आरईएस/49/115 में बंजर और सूखे से जुड़े मुद्दे पर जन जागरुकता को बढ़ावा देने और सूखे या मरुस्थलीकरण का दंश झेल रहे देशों के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की घोषणा की।

3. अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस

- हर साल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस (International Day of Family Remittances) मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून, 2015 में मनाया गया था। यह दिन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को प्रवासियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और प्रेषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु से संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है।

अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस (IDFR) का उद्देश्य

- इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उन प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना है जिसमें कि श्रमिकों द्वारा दिये गये इन योगदानों से लाखों परिवारों, समुदायों, देशों और क्षेत्रों पर भी पड़ता है।
- इसके अलावा IDFR सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और नागरिक समाज से भी ऐसे तरीके खोजने का आग्रह करता है जो व्यक्तियों और सामूहिक कार्यों के लिए प्रेषण के रूप में किए गए योगदान के प्रभाव को अधिकतम कर सकें।
- विदित हो कि वर्ष 2019 में, भारत को 3

बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ था। यह 2020 में 0.2% तक गिर गया। यह संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषण में अधिकतम था। यूएई से भारत में प्रेषण 17% कम हो गया है। वहीं पाकिस्तान में, प्रेषण में 17% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान के लिए प्रेषण में सबसे बड़ी वृद्धि सऊदी अरब से हुई।

4. अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिजम जागरूकता दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय ऐल्बिनिजम जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। इस दिन को ऐल्बिनिजम से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने और पैदा करने के लिए चिह्नित किया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम #Strength Beyond All Odds है।
- इस विषय को चुनने का कारण मुख्य रूप से दुनिया भर में ऐल्बिनिजम वाले लोगों के अच्छे गुणों को उजागर करना है। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे ऐल्बिनिजम वाले लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी बाधाओं को दूर करने और अपेक्षाओं को पार करने के लिए जागरुक किया जाता है।

ऐल्बिनिजम क्या है?

- यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आँखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता। ऐल्बिनिजम किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसका कोई उपचार नहीं है। त्वचा में मेलेनिन न होने के कारण प्रभावित व्यक्ति सनबर्न तथा त्वचा कैंसर से पीड़ित हो सकता है। यह फोटोफोबिया, अम्ब्लायोपिया, निस्टैगमस जैसे चक्षु रोग से भी सम्बंधित है।
- ऐल्बिनिजम से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पर सफेद धब्बे होते हैं अथवा कई बार पुरी त्वचा ही सफेद हो जाती है। इसके कारण ऐल्बिनिजम से पीड़ित लोगों को कई प्रकार

के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **मेलेनिन:** यह एक किस्म का जटिल पॉलीमर होता है, यह एमिनो एसिड टायरोसीन से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा त्वचा तथा बालों का रंग निर्धारित होता है।

5. विश्व शरणार्थी दिवस

- विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के बीच UN ने विश्व शरणार्थी दिवस 2021 के थीम "Together we can achieve anything" यानि 'हम सब मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं।' रखा गया है। जबकि बीते वर्ष 2020 में विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम, स्टेप विद रिफ्यूजी (Step with Refugees) रखी गई थी।

विश्व शरणार्थी दिवस का इतिहास

- हर साल 20 जून को विश्व भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि पहले यह इस दिन नहीं मनाया जाता था। 4 जून 2000 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN ने इसे मनाने की घोषणा की। इसे मनाने के लिए 17 जून तारीख तय की गयी। इसके अगले साल, 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने पाया कि इस वर्ष 1951 के शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन (1951 Convention relating to the Status of Refugees) के 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद यह दिन 17 की बजाय 20 जून को पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तब से ही हर साल यह दिन 20 जून को ही मनाया जाता है।

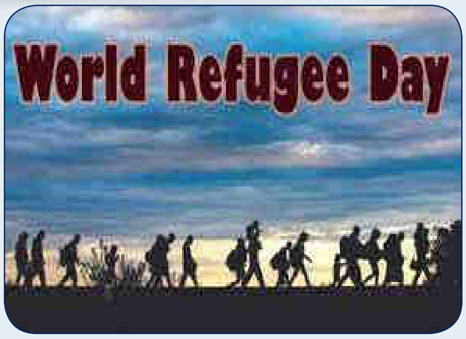

6. विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए फिक्की, नोवार्टिस, पिरामल फाउंडेशन, अपोलो अस्पताल, एनएएससीओ और जीएएससीडीओ के साथ साझेदारी में श्भारत में सिकल सेल रोगश पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
- विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर, 2008 को सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।

मुख्य बिंदु

- यह एक अनुवांशिक रोग है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार के बजाय दरांती (sickle) के आकार की होती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरुरत पड़ती है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार हैं: सांस लेने में तकलीफ,कमजोर प्रतिरक्षण क्षमता, बार-बार संक्रमण होना, शरीर का कम विकास, देखने में कठिनाई तथा हाथ व पैर में सूजन।

सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease& SCD)

- सिकल सेल रोग (SCD) या सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) लाल रक्त कोशिकाओं से जुडी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्र/हंसिया (Sickle) जैसा हो जाता है। ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ (Red Blood Cells- RBCs) कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में

फँस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। यह आसामान्य आकार RBCs के जीवनकाल को भी कम करता है तथा एनीमिया (रक्ताल्पता) का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

- योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम 'बी विद योग, बी, एट होमश यानी श्योग के साथ रहें, घर पर रहें' रखी गई है।

21 जून को क्यों मनाया जाता है योग दिवस

- 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इस वजह से इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात रखी थी। बाकी सभी देशों ने भी इसका समर्थन किया था। इसके बाद से 21 जून को योग के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस माने की घोषणा की थी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत (History)

- योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग हैं। इसका सर्वाधिक प्रचार स्वामी विवेकानन्द जी ने किया था। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून

को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 27 सितम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में अपने भाषण में की। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के लिए हामी भर दी।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय सेना ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) के रेवाड़ी-मदार खंड (Rewari - Madar section) में वाहनों और उपकरणों से भरी सैन्य गाड़ी को ले जाकर सफल परीक्षण किया है।

2. मुख्य बिन्दु

- भारतीय सेना ने हाल ही में डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Rail Freight corridor -DRFC) की प्रभावकारिता को मान्य करते हुए न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक वाहनों और उपकरणों से भरी सैन्य गाड़ी को ले जाकर सफल परीक्षण किया है।
- यह परीक्षण राष्ट्रीय संसाधनों को अनुकूलित करने और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बाधारहित तालमेल के लिए 'हॉल ऑफ द नेशन एप्रोच' का हिस्सा था।
- यह परीक्षण सशस्त्र बलों की अभियान सम्बंधी तत्परता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इसके माध्यम से यह सुनिश्चित हुआ है कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सैन्य आवश्यकताओं का आपसी मेलजोल समय की जरूरत है।

3. डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर (DRFC)

- डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Rail Freight corridor-DRFC), रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत भारत में रेल के द्वारा मालवहन को अधिक सुगम बनाया जाना लक्ष्य है।
- इस परियोजना में नई रेल लाइनों के विकास का लक्ष्य है। जिसके ऊपर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी यानि मालवाहक रेल लाइनों व यात्री रेल लाइनों दोनों को एक दूसरे से अलग करने की योजना है।
- इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड' (Dedicated Freight Corridor Coporation of India Limited -DFCCIL) की है जो कि रेल मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- प्रथम गलियारे का नाम 'ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (Eastern Dedicated Freight Corridor-EDFC) और दूसरे गलियारे का नाम 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) है।
- जहाँ पूर्वी गलियारा पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ता है वहीं पश्चिमी गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी को महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट से जोड़ता है।
- पूर्वी गलियारा लगभग 1856 किलोमीटर लम्बा तथा पश्चिमी गलियारा लगभग 1504 किलोमीटर लम्बा है।

4. आवश्यकता क्यों?

- भारत में जनसंख्या बोझ व खराब आधारभूत संरचना के कारण, रेलगाड़ियों का समय से न चल पाना आम बात हो गई है।
- इसके अलावा, रेल मंत्रालय द्वारा हर साल नई रेलगाड़ियों को चलाये जाने व अपर्याप्त रेल लाइनों की वजह से रेल ट्रैफिक (Rail Traffic) की समस्या गम्भीर होती जा रही है।
- इसी कारण से मालगाड़ियों व यात्रीगाड़ियों को दूसरे के लिये रूककर पास देना पड़ता है जिससे गाड़ियाँ अपने तय समय पर गंतव्य तक नहीं पहुँच पाती है। इन्ही कारणों की वजह से भारत में मालगाड़ियों की औसत गति लगभग 25 किमी प्रति घण्टा व यात्रीगाड़ियों की औसत गति लगभग 50 किमी प्रति घण्टा की है।
- भारत में माल ढुलाई आज भी काफी मंहगी है, यही कारण है कि भारत का निर्यात काफी मंहगा हो जाता है और भारतीय वस्तुएँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्पर्द्धा नहीं कर पाती हैं।
- भारत में लाजिस्टिक कीमतों को कम करने में डीएफआरसी (DRFC) की अति आवश्यकता है।

5. प्रभाव

- इन नये गलियारों के बनने की वजह से जहाँ एक और रेल लाइनों पर दबाव कम होगा वहीं दूसरी ओर यातायात में लगने वाला समय भी कम होगा।
- आंकड़ों के मुताबिक, इन गलियारों की वजह से मालगाड़ियों की औसत गति बढ़कर 80 से 85 किमी प्रति घण्टा हो जायेगी।
- मालगाड़ियों से ढुलाई में देरी की वजह से उनमें रखा सामान खराब हो जाता था जिससे फल, सब्जियाँ, दूध व अन्य खाद्य सामग्रियों को रेल परिवहन के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता था। इन गलियारों के बनने से ऐसी समस्यायें दूर हो जायेंगी।
- भारत में बढ़ते ई-कामर्स बाजार (e-commerce market) के लिये ये गलियारे वरदान साबित होंगे। ई-कामर्स कंपनियाँ अब सामान की डिलीवरी के लिये रेलवे का उपयोग कर पायेंगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही बड़े बंदरगाहों के आपस में जुड़ने की वजह से यातायात व माल परिवहन में सुगमता होगी।

02 टीबी की रोकथाम में तेजी लाने के लिए वैश्विक अभियान

1. चर्चा में क्यों

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डब्ल्यूएचओ वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम द्वारा आयोजित टीबी की रोकथाम में तेजी लाने के लिए वैश्विक अभियान पर वर्चुअल उच्चस्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लियें।

2. उद्देश्य

- इस विशेष उच्चस्तरीय आयोजन का उद्देश्य, टीबी रोकथाम की रणनीतियों को विस्तार देने और टीबी निवारक उपचार पर 2022 संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर जरूरी प्रमुख कदमों पर चर्चा करना था।

3. भारत की स्थिति

- भारत टीबी का मुकाबला करने और 2025 तक उसके खात्मे के लिए नए टीबी निवारक उपचार के रास्ते पर चल रहा है।
- भारत की प्रतिबद्धताओं को दृढ़ता के साथ दोहराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत टीबी को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को आक्रामक ढंग से लागू कर रहा है।
- पांच करोड़ लोगों का उपचार कर पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक (यूएनएचएलएम) के लक्ष्यों- वैश्विक स्तर पर टीबी के उपचार का 4 करोड़ और टीपीटी पर 3 करोड़ लोगों, को हासिल करने के लिए शेष 18 महीनों में भारत राष्ट्रीय स्तर पर टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) और गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सटीक टीबी स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टूल जैसे एनएएटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन के साथ डिजिटल एक्स-रे, उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बहु-क्षेत्रीय सामुदायिक जुड़ाव के साथ हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर एकीकृत टीबी सेवाएं देश में टीबी के मामलों और मृत्यु दर में तेजी से कमी लाने के लिए हैं।
- भारत ने 2025 तक यानी 2030 के एसडीजी लक्ष्य से पांच साल पहले ही टीबी को समाप्त करने की अभूतपूर्व राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है।
- स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत ने 2020 में स्थापित राज्यों और जिलों के उप-राष्ट्रीय प्रमाणन पर भी बात की। इस पहल में विभिन्न श्रेणियों के तहत 'टीबी मुक्त दर्जे की दिशा में प्रगति' पर जिलों/राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है, जिसे टीबी की घटनाओं में गिरावट के हिसाब से मापा जाता है।
- उनके अनुसार केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले को 2020 में देश में पहले टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश और पहले टीबी मुक्त जिले के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है।

4. भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020

- वर्ष 2019 में लगभग 04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में यह 14% की वृद्धि है।
- वर्ष 2017 में टीबी रोगियों के 10 लाख से अधिक गैर-अधिसूचित मामले थे, जो घटकर 9 लाख हो गए हैं।
- निजी क्षेत्र में 35% की वृद्धि के साथ 78 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2018 में 6% की तुलना में 2019 में टीबी से ग्रसित बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया है।
- सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की एचआईवी जांच, वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गई है।
- उपचार सेवाओं के विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% सुधार हुआ है। 2018 में 69% की तुलना में 2019 के लिए यह दर 81% है।

5. टीबी (TB) के बारे में

- टीबी या तपेदिक / क्षय रोग, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर्क्युलोसिस (Bacillus Mycobacterium tuberculosis) नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।यह आमतौर पर फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी- pulmonary TB) को प्रभावित करता है, किंतु यह इसके अलावा मानव-शरीर के अन्य अंगो को भी प्रभावित कर सकता है। यह बीमारी, फुफ्फुसीय टीबी से पीड़ित व्यक्ति की खांसी या किसी अन्य माध्यम से वायु में बैक्टीरिया पहुँचने से फैलती है।

03 गहरे समुद्र मिशन को अनुमति

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'गहरे समुद्र मिशन' को अनुमति प्रदान कर दी, जिससे समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई।

2. 'डीप ओशन मिशन' के बारे में

- अभी दुनिया के पांच देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन के पास ही ये तकनीक है।
- 'गहरे समुद्र मिशन' (Deep Ocean Mission) के तहत, 35 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किये गए अंतरिक्ष अन्वेषण की भांति, गहरे महासागर में अन्वेषण करने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह मिशन, गहरे समुद्र में खनन, समुद्री जलवायु परिवर्तन संबंधी सलाहकारी सेवाओं, अन्तर्जलीय वाहनों एवं अन्तर्जलीय रोबोटिक्स संबंधी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा।
- इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी।
- इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) नोडल मंत्रालय होगा।

3. इस अभियान के 6 प्रमुख घटक

- तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। मध्य हिंद महासागर में इस गहराई से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
- सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की जैव-पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन करना।
- इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है।
- अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) विलवणीकरण संयंत्र के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना।
- इस घटक का उद्देश्य महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम का विकास करना है।
- यह घटक ऑन-साइट बिजनेस इन्क्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा।

4. संभावना

- पृथ्वी का 70 प्रतिशत हिस्सा समुद्र है। उसके बारे में अभी बहुत अध्ययन नहीं हुआ है।
- इस मिशन का मकसद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (PMN) की खोज करना और उन्हें निकालना है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर की करीब 6000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बिखरे पड़े हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है।
- समुद्र तल में भारी मात्रा में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लेटिनम समेत बहुत सारे खनिज मिलने की संभावना है।
- इससे मिलने वाली धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सोलर पैनल में हो सकता है।
- भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स (Polymetallic nodules- PMN) अन्वेषण के लिये 'संयुक्त राष्ट्र सागरीय नितल प्राधिकरण' द्वारा 75,000 वर्ग किलोमीटर का आवंटन किया गया है।

5. लाभ

- इससे एक तरफ ब्लू इकनॉमी को मजबूती मिलेगी, साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी।
- इससे समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी।
- गहरे समुद्र मिशन का एक बढ़ा फायदा ये भी होगा कि इससे हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी।
- इस मिशन से खुद प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- इससे एमएसएमई क्षेत्र के लिए नए मौके पैदा होंगे।
- साथ ही अनुसंधान के नए अवसर भी आएंगे।
- इस मिशन से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी।

6. पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स (PMN) के बारे में

- पॉली-मैटेलिक नॉड्यूल्स जिन्हें समान्यतः मैंगनीज नॉड्यूल्स भी कहा जाता है, आलू के आकार का तथा प्रायः छिद्रयुक्त होते हैं। ये विश्व महासागरों में गहरे समुद्र तलों पर प्रचुर मात्रा में बिछे हुए पाए जाते हैं। पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स में मैंगनीज और लोहे के अलावा, निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम पाए जाते हैं, जिनमें से निकल, कोबाल्ट और तांबा आर्थिक और सामरिक महत्व के माने जाते हैं।

04 बासमती के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ से बासमती चावल के लिए 'संरक्षित भौगोलिक संकेतक' (Protected Geographical Indication– PGI) दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया है। वहीं पाकिस्तान यूरोपीय संघ में भारत के इस आवेदन का विरोध कर रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारत के बासमती चावल के जीआई टैग के दावे को पाकिस्तान इस तर्क पर खारिज करता है कि उसके देश में भी बासमती उगाया जाता है।
- जानकारों का कहना है कि भारत के बासमती को जीआई टैग मिलने का मतलब है कि फिर दुनियाभर में यही माना जाएगा कि असली और सबसे अच्छी गुणवत्ता का बासमती सिर्फ भारत में पैदा होता है। इसका असर पाकिस्तान के बासमती निर्यात पर पड़ेगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भारत ने अपने देश में बासमती चावल का जीआई रजिस्ट्रेशन करा लिया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और वह बगैर जीआई टैग के ही बासमती चावल की बिक्री करता रहा, जिसकी वजह से दूसरे देशों में भारतीय बासमती चावल के मुकाबले पाकिस्तान के बासमती को कारोबार के मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ा।

3. क्यों जरूरी है जीआई ?

- एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र वाले उत्पाद के लिए जियोग्राफिकल इंडीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ यह कि उत्पत्ति की विशेष भौगोलिक पहचान से जोड़ने के लिए किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है।
- उत्पाद को दूसरों से अलग और खास बनाए रखने के साथ ही विशिष्ट पहचान कायम रखने के लिए जीआई टैग महत्वपूर्ण है।
- विदित हो कि मूल क्षेत्र के होने की वजह से ऐसे उत्पादों की विशिष्टता एवं प्रतिष्ठा होती है। जीआई टैग की वजह से किसी खास उत्पाद के साथ गुणवत्ता खुद ही जुड़ जाती है।
- जीआई टैग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के 'अग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंट्लेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स' (TRIPS) के जरिए हासिल किया जाता है। साथ ही, कई देशों में अपनी संस्थाएं भी हैं, जो घरेलू स्तर पर चीजों को जीआई टैग देती हैं। धीरे-धीरे ये व्यवस्था ऐसी बनी कि वैश्विक जीआई टैग हासिल करने के लिए पहले अपने ही देश में उस चीज को जीआई टैग मिलना जरूरी है।

4. जीआई टैग का उद्देश्य

- जीआई टैग का मकसद आज भी वही है। चीजों की गुणवत्ता बरकरार रखना। फर्जी दावों से चीजों की बिक्री रोकना, उत्पादकों के हितों और ग्राहकों को मिलने वाली गुणवत्ता की रक्षा करना।

5. बासमती का इतिहास

- जब भारत राइसटेक कंपनी के खिलाफ अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, तब अपने दावे के पक्ष में भारत ने 50 हजार पन्नों के दस्तावेज पेश किए थे। इन पन्नों में एक जिक्र ये भी था कि बासमती भारत में सोहनी-महिवाल के वक्त से उगाया जा रहा है। सोहनी-महिवाल सिंध-पंजाब प्रांत की एक दुखद प्रेम कहानी है, जिसका जिक्र 18वीं सदी से मिलता है।
- भाषाविद् बताते हैं कि बासमती शब्द संस्कृति के वस (Vas) और मायप (mayup) शब्दों से मिलकर बना है। वस का अर्थ सुगंध और मायप का अर्थ है 'गहरे तक जमा हुआ'। बताते हैं कि ये 'मायप' बाद में 'मती' हो गया, जिससे चावल को 'बासमती' नाम मिला। 'मती' का एक अर्थ 'रानी' भी बताया जाता है, जिससे बासमती का अर्थ बनता है 'सुगंध की रानी'। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दर्ज 'Basmati' हिंदी के बासमती से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुगंध होता है।

6. भारत-पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है बासमती?

- दुनिया में जितना चावल पैदा होता है, उसका 90 फीसदी उत्पादन और खपत एशिया में होती है। चावल की पैदावार में भारत दुनिया में दूसरे और निर्यात करने में पहले नंबर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया का करीब 65 फीसदी बासमती निर्यात करता है, जबकि बचे हुए मार्केट पर पाकिस्तान का कब्जा है।
- बासमती दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम योगदान अदा करता है। चूंकि इस मार्केट में भारत-पाकिस्तान के अलावा कोई और खिलाड़ी है नहीं, इसलिए दोनों देशों के बीच बाजार में बड़े कब्जे की होड़ भी है। जीआई टैग का संघर्ष इसी होड़ का नतीजा है।

05 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं पर बोझ कम करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. नए संशोधित प्रावधान

- केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर दिए जाने वाले इन्सेंटिव कैप को मौजूदा 20 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।
- इसी तरह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों पर मिलने वाले डिमांड इन्सेंटिव में भी पचास फीसदी की बढ़ोतरी कर उसे 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा कर दिया है। सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के कीमत में काफी कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- फेम-2 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है जिसमें से, दोपहिया वाहनों को विशेष रूप से ई-स्कूटर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि हर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

3. फेम इंडिया फेस टू

- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के इरादे से केंद्र सरकार ने 2019 में फेम इंडिया फेस टू को लॉन्च किया था. इसके तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था।
- 'फेम इंडिया' नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (NEMM) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 'फेम' का मुख्य जोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
- भारत में अप्रैल 2015 में FAME (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (NEMM) के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। द्वितीय FAME योजना पहले चरण की विस्तारित योजना है और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को तेजी से अपनाना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग और बुनियादी ढांचे को स्थापित करना है।
- FAME 2 इंडिया का चरण 1 संस्करण 1 अप्रैल, 2015 को 895 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था, जो 31 मार्च, 2019 को पूरा हो गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया और तिपहिया पर फेम इंडिया योजना के तहत प्रोत्साहन करना है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जोर दिया जा सके।
- इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इतना ही नहीं, यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की सुरक्षा के मुद्दे को दूर करने में भी मदद करेगी। इस योजना का चरण द्वितीय अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च, 2022 तक पूरा किया जाना है।

4. FAME II योजनाः सुविधाएँ

- इस योजना का जोर सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर है जिसमें साझा परिवहन शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए, परिचालन व्यय पर मांग प्रोत्साहन राज्य / शहर परिवहन निगम (एसटीयू) के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से, 10 लाख ई -2 डब्ल्यू, 5 लाख ई -3 डब्ल्यू, 55000 4 डब्ल्यू और 7000 बसों का समर्थन करने की योजना है।
- सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों, तिपहिया वाहनों और चार पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी।
- इस स्कीम में प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के साथ बड़ी मात्रा में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर को भी शामिल किया जाएगा।

06 दक्षिणी महासागर

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका (National Geographic magazine) ने विश्व महासागर दिवस (8 जून) के मौके पर 'दक्षिणी महासागर' को दुनिया के पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दी है।

2. प्रमुख बिन्दु

- दक्षिणी महासागर वास्तव में अंटार्कटिका के आसपास का महासागरीय इलाका है। यह बहुत लंबे समय से विवाद का विषय रहा है कि क्या इस महासागरीय क्षेत्र को अलग नाम दिया भी जाए या नहीं। इसीलिए अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग से महासागर घोषित नहीं किया जा सका था।
- अंटार्कटिका के आसपास का 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का इलाका दक्षिणी महासागर कहलाएगा। इसमें डार्क पैसेज और स्कोटिया सागर शामिल नहीं होगा।
- इसके अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (Antarctic Circumpolar Current, ACC)) द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया है जिसका विकास 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मझासागरीय धाराएँ प्रवाहित होती है।

3. अंटार्कटिका सर्कम्पोलर करंट

- अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC) अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, एक व्यापक उतार-चढ़ाव वाले बैंड में, जो लगभग 60 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के आसपास केंद्रित है। यह वह रेखा है जिसे अब दक्षिणी महासागर की उत्तरी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। ACC के अंदर, पानी ठंडा है और उत्तर में समुद्र के पानी की तुलना में थोड़ा कम खारा है।
- सतह से समुद्र तल तक फैले हुए, ACC किसी भी अन्य महासागरीय प्रवाह की तुलना में अधिक पानी का परिवहन करता है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों से पानी खीचता है, जिससे एक वैश्विक परिसंचरण प्रणाली को चलाने में मदद मिलती है जिसे कन्वेयर बेल्ट (Conveyor belt) के रूप में जाना जाता है, जो ग्रह के चारों ओर हीट का परिवहन करता है।
- वैज्ञानिक वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं कि मानव संचालित जलवायु परिवर्तन दक्षिणी महासागर को कैसे बदल रहा है।

5. इंटरनेशल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन

- इंटरनेशल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन (IHO) ने वर्ष 1937 में अपने दिशानिर्देशों में दक्षिणी महासागर को मान्यता दी लेकिन विवाद के कारण 1953 में इस पदनाम को निरस्त कर दिया गया। उसने इस मामले पर तब से विचार-विमर्श कर रहा है, लेकिन अभी तक दक्षिणी महासागर को बहाल करने के लिए अपने सदस्यों से पूर्ण सहमति प्राप्त नहीं हुई थी।
- साल 1999 में नेशनल ओसियानिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOA) ने भी दक्षिणी महासागर को पांचवे महासागर के तौर पर पहचान दी थी। लेकिन साल 2000 में इंटरनेशल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन (IHO) इससे सहमत नहीं हुई। विदित है कि IHO ही सभी सागरों, महासागरों और संचालन पानी का सही तरीके से सर्वे करने के बाद उसका नक्शा बनाता है।

4. मान्यता का महत्व

- दक्षिणी महासगर में बेहद अनोखे और नाजुक जलीय ईकोसिस्टम (Aquatic Ecosystem) पाए जाते हैं जहां वेल, पेंग्विन्स और सील्स जैसे जीव रहते हैं। ऐसी हजारों प्रजातियां हैं जो सिर्फ यहीं रहती हैं, और कहीं नहीं पाई जातीं।
- इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों का काफी असर पड़ा है। क्रिल (Krill) और पैटागोनियन (Patagonian) टूथफिश जैसी प्रजातियों पर औद्योगिक मछली पकड़ने का प्रभाव दशकों से दक्षिणी महासागर में एक चिंता का विषय रहा है। ऐसे में संरक्षण की जरूरत के चलते भी इसे अलग से मान्यता देना अहम हो जाता है।
- दक्षिणी महासागर का पारिस्थितिक प्रभाव कहीं और भी है। कुछ समुद्री पक्षी अंदर और बाहर भी प्रवास करते हैं। दक्षिणी महासागर की ओर ध्यान आकर्षित करके, नेशनल ज्यॉग्रैफिक सोसाइटी इसके संरक्षण को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है।

07 डगमारा जलविद्युत परियोजना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (National Hydro Power Corporation-NHPC) लिमिटेड ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- बिहार की 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना को एनएचपीसी की स्वामित्व के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।
- गौरतलब है कि जल विद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी-ए की एक मिनीरत्न कंपनी है। वर्तमान में, एनएचपीसी के पास 24 परिचालित विद्युत स्टेशन हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है।
- यह परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकार में इसलिए लंबित थी कि इसकी परियोजना लागत अधिक है।

3. इस परियोजना के बारे में

- यह परियोजना कोसी नदी पर बनायी जा रही है। कोसी नदी के तटबंध पर इस परियोजना की शुरुआत होगी।
- डगमरा पनबिजली परियोजना का डीपीआर दिसंबर 2011 में ही केंद्र को सौंपा गया था। इसमें पनबिजली के साथ-साथ सौर ऊर्जा, मछली उत्पादन को भी शामिल किया गया है।
- बिहार के साथ-साथ बिजली की आपूर्ति नेपाल को भी की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए 5 वर्षो की अवधी के दौर कुल 700 करोड़ रु० अनुदान के रूप में स्वकृत किया गया। ₹700 करोड़ के अनुदान से परियोजना के निर्माण लगता में काम आई जिस से राज्य को सस्ती बिजली प्राप्त होगी।
- परियोजना के निर्माण से बाढ़ के विभीषका से होने वाली जान माल एवं तटबंध की क्षति में कमी आएगी तथा कोसी नदी को पार करने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग पुल का निर्माण हो सकेगा, जिससे एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा।
- डगमारा बहुउद्देशीय जल विधुत परियोजना रन आफ रिवर के अंतर्गत कोशी बराज से लगभग 31 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मे कोसी नदी पर भप्तियाही ब्लाक जिला सुपौल में बनाया जाना है।
- इस परियोजना की कुल क्षमता 130 मेगावाट है जिसमें 7.65 मेगावाट के 17 यूनिट स्थापित होगी जिसमें 5.87 मीटर का हेड विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा। इस परियोजना में कंक्रीट बराज, अर्थन डैम एवं पावर हाउस का निर्माण किया जाना है जिसकी लम्बाई क्रमशः 945 मीटर,5750 मीटर, एवं 283.20 मीटर होगी।

4. परियोजना से लाभ

- इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक हजार से 12 सौ व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- परियोजना के पूर्ण होने पर कोसी नदी पर एक और पुल का विकल्प उपलब्ध होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करना सुगम होगा।
- पर्यटन एवं मत्स्य पालन के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही इस क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

5. कोसी नदी

- कोसी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है जो सात नदियों- इंद्रावती, सुनकोसी या भोट कोसी, तांबा कोसी, लिक्षु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामर कोसी के सम्मिलित प्रवाह से बनी है।
- त्रिवेणी के पहाड़ों से होते हुए कोसी हनुमान नगर के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहाड़ से मैदान में उतरते ही कोसी का पाट काफी चौड़ा होता जाता है।
- कोसी नदी बिहार में कुल 260 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 74,073 वर्ग किमी है, जिसमें 11, 410 वर्ग किमी क्षेत्र बिहार में है।
- कोसी अपनी धारा लगातार बदलने के लिए प्रसिद्ध है. इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

तुलु (Tulu) भाषा

प्र. तुलु (Tulu) भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने वाले लोग दक्षिण भारत में रहते हैं।
2. जिन क्षेत्रों में तुलु भाषा प्रधानत: बोली जाती है उसे बोलचाल की भाषा में तुलु नाडु कहा जाता है।
3. इसके अंतर्गत मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय जिले और केरल का कासरगोड जिला आता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

ऑपरेशन मोलिविया

प्र. ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था।
2. यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।
3. यह ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है जब वे नवंबर से दिसंबर के महीनों में प्रजनन के लिए ओडिशा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (B)

पासिफए (PASIPHAE) परियोजना

प्र. हाल ही में चर्चित पासिफए (PASIPHAE) परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. PASIPHAE से तात्पर्य पोलराइजेशन हाई-एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट में पोलर-एरिया स्टेलर-इमेजिंग है।
2. यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है।
3. वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र में उच्च-स्तरीय संवाद

प्र. हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय संवाद' में संबोधन दिया इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत के प्रधानमंत्री ने 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया है।
2. भारत, भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की राह पर है।
3. भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल

प्र. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत का राष्ट्रीय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल' इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
2. यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

47वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2021

प्र. हाल ही में संपन्न 47वां जी-7 शिखर सम्मेलन, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया।
2. इस वर्ष बिल्ड बैक बेटर विषय पर चर्चा की गयी।
3. जी-7 देशों ने स्पष्ट किया कि चीन एक प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी, वैश्विक मुद्दों पर एक भागीदार और एक प्रतियोगी है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त सभी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

दुर्लभ मृद्रा तत्व

प्र. दुर्लभ मृदा तत्त्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. दुर्लभ मृदा तत्त्व 17 दुर्लभ धातु तत्त्वों का समूह है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते हैं।
2. इनमें आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड और स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं।
3. इनका प्रयोग पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान और हथियार प्रणालियों जैसे बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त सभी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

महाराष्ट्र में पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा

प्र. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा दिया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षणके लिए महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 100वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज (धरोहर) का दर्जा देकर संरक्षित करने का फैसला किया है।
2. इसके लिए महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम' 1875 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (D)

CHIME टेलीस्कोप एवं फास्ट रेडियो बर्स्ट

प्र. 'CHIME टेलीस्कोप' एवं 'फास्ट रेडियो बर्स्ट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ये बहुत ही चमकीली रेडियो तरंगें होती हैं जो कुछ ही मिली सेंकंड में खत्म हो जाती हैं।
2. ये संक्षिप्त और रहस्यमयी प्रकाश-दीप्तियाँ, ब्रह्मांड के विभिन्न और दूरस्थ हिस्सों के साथ-साथ हमारी अपनी आकाशगंगा में भी देखीं जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

दिल्ली मास्टर प्लान 2041

प्र. हाल ही में चर्चित दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के मसौदे में दो खंड और 22 अध्याय शामिल हैं, जो वर्ष 2041 तक दिल्ली को स्थायी, रहने योग्य और जीवंत बनाने हेतु तैयार करना है।
2. किसी भी शहर का मास्टर प्लान शहर के नियोजकों और भू-स्वामी एजेंसी के विजन डॉक्युमेंट की तरह होता है, जो भविष्य के विकास को दिशा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति

प्र. नागालैंड में नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. नागालैंड सरकार ने केंद्र के साथ नागा शांति समझौते और राजनीतिक मुद्दों के समाधान लिए विपक्षी नेताओं की एक समिति गठित करने का फैसला किया है।
2. इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नेफियू रियो करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का 'बीड मॉडल'

प्र. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 'बीड मॉडल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित, बीड जिला किसी भी बीमा कंपनी के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
2. इसकी वजह यह है कि यहां के किसान बार-बार बारिश नहीं होने या भारी बारिश के कारण अपनी फसल गंवा देते हैं।
3. राज्य सरकार को बीड जिला में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त सभी

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

शुक्र ग्रह के लिये एनविजन मिशन

प्र. हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने शुक्र ग्रह के लिये एक नए एनविजन मिशन (EnVisionmission) की घोषणा की है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) का भी योगदान होगा।
2. इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किये जाने की संभावना है।
3. इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
4. इस अंतरिक्षयान को शुक्र तक पहुँचने में लगभग 15 महीने लगेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 3 और 4

(C) केवल 1 और 3

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

शिक्षा मंत्रालय का ऑनलाइन मॉड्यूल

प्र. शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान सत्र 2021-22 में पहली बार 16-18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा को मुक्त / दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से जारी रखा जा सके।
2. स्कूल न जाने वाले चिह्नित प्रत्येक बच्चे की और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी प्रखंड संसाधन समन्वय के तहत प्रखंड स्तर पर अपलोड होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

उड़ीसा का राज/राजा पर्व

प्र. रज पर्व अथवा राजा परबा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह ओडिशा में नारीत्व का जश्न मनाने का तीन दिवसीय त्योहार है।
2. ऐसा माना जाता है कि पहले तीन दिनों में धरती माता मासिक ध र्म से गुजरती है।
3. उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है- मासिक धर्म।

उपर्युक्त कथनों में से कौन / सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त सभी

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

❖❖❖

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

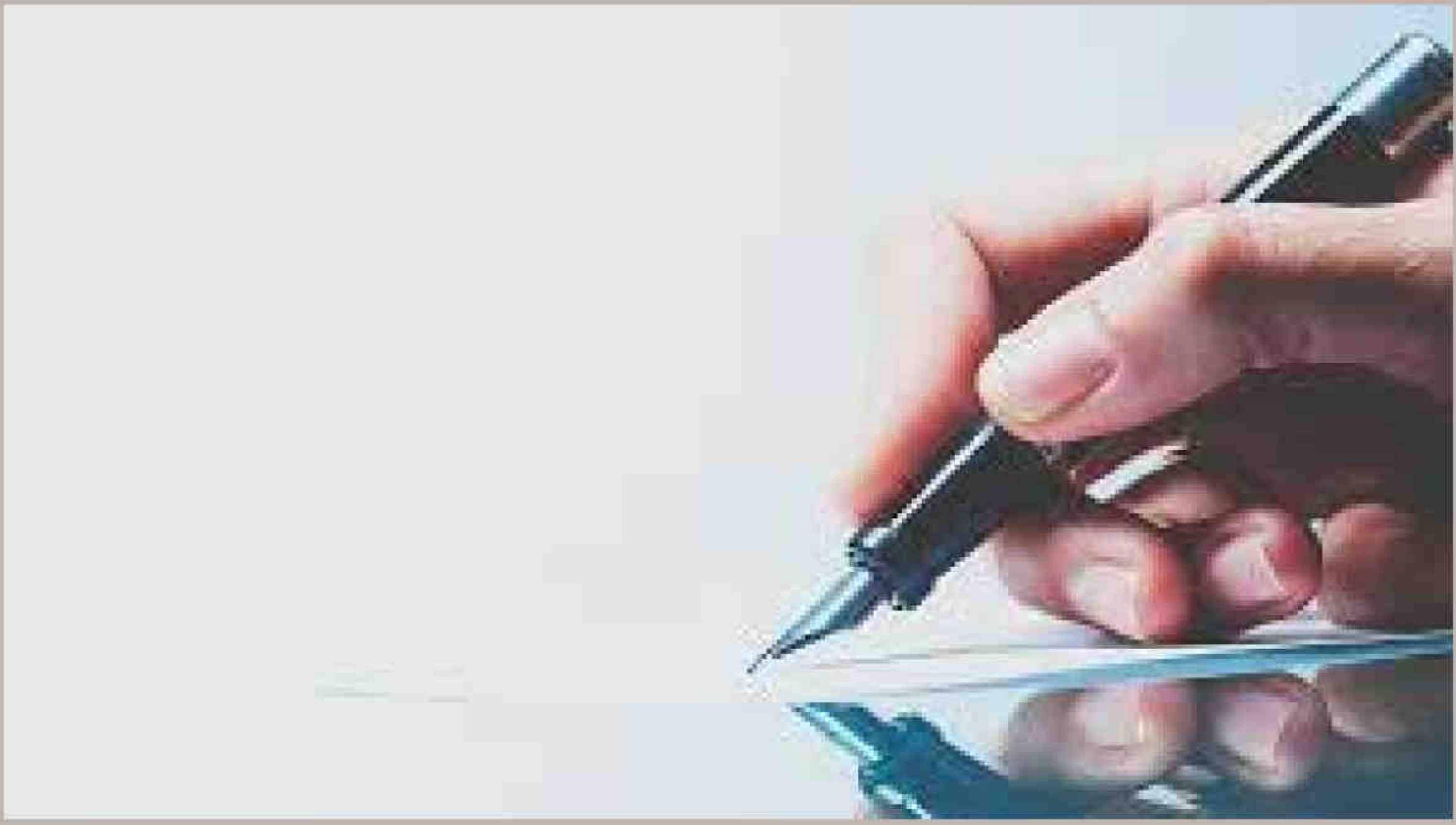

01

04

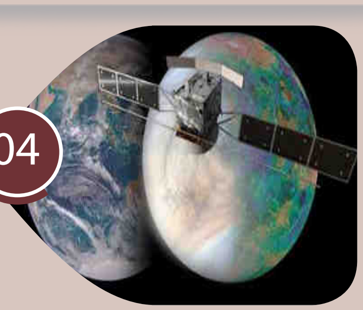

07

01 CHIME फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? यह ब्रह्माण्ड के सदस्यों को समझने में किस प्रकार सहायक है?

02 हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मसौदे की चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करें।

03 प्रधानमंत्री फसल बीमा का 'बीड मॉडल' क्या है? यह मॉडल किसानों के लिए कितना हितकर है?

04 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 'एनविजन मिशन' के बारे में बताते हुए इस मिशन की उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

05 हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन मॉड्यूल क्या शिक्षा जगत को एक नया स्वरूप प्रदान कर पाएगा? टिप्पणी करें।

06 हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा 'राजा परबा' उत्सव मनाया गया। यह उत्सव महिलाओं को जागरूक करने में किस प्रकार सहायक होगा? उल्लेख करें।

07 ऑपरेशन 'ओलिविया' क्या है? यह कछुओं के संरक्षण में कहाँ तक कारगर है? विवरण दें।

08 'पासिफायें (PASIPHAE)' परियोजना क्या है? यह आकाशीय घटनाओं का किस प्रकार सर्वेक्षण करेगा?

09 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल' के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

10 हाल ही में जी-7 का वर्चुअल रूप से 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जी-7 के संदर्भ में इस शिखर सम्मेलन की उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

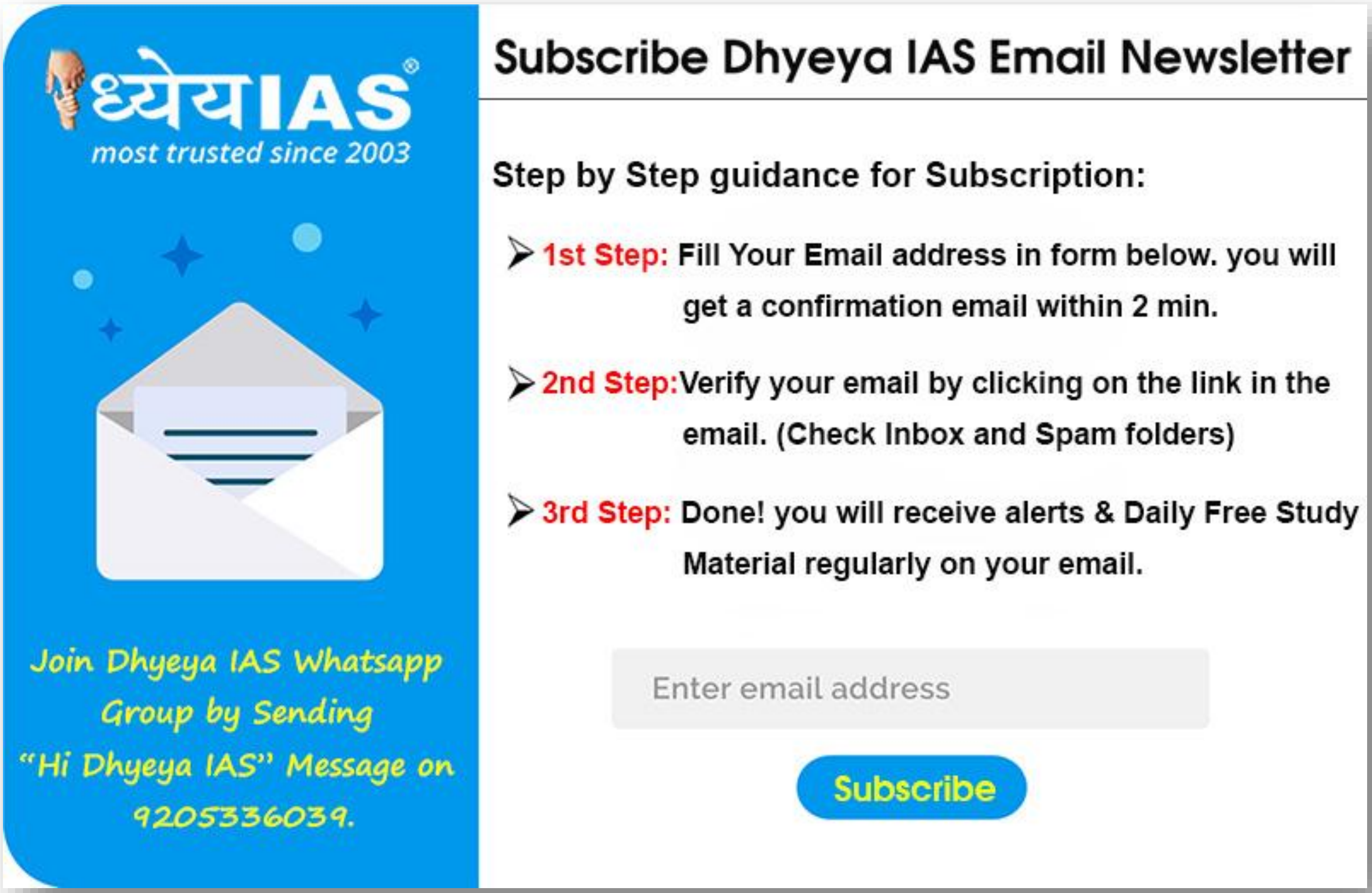

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com